सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

वर्ष-01 अंक-144 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शनिवार 13 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए

सु-विचार

"इंसान विकल्पों का आदी है, विकल्प मिलते ही उसे नये में खूबियां और पुराने में खामियां नजर आने लगती हैं...!!"

अज्ञात...

सूरज की रोशनी से चमका जिला राजनांदगांव, सोलर ऊर्जा का बना राष्ट्रीय मॉडल

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में देश में सबसे ज्यादा सोलर क्षमता, ढाबा में लगा 160 मेगावाट का सबसे बड़ा कनेक्शन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले ने देशभर में नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राजनांदगांव देश में सर्वाधिक सोलर क्षमता वाले कनेक्शन स्थापित करने वाला जिला बन गया है। शहरों के साथ गांवों में भी सौर ऊर्जा को लेकर लोगों का उत्साह तेजी से बढ़ रहा है।

6776 आवेदन, 3255 घरों में रूफटॉप सोलर

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के समन्वित प्रयासों से यह सफलता मिली है। योजना के तहत जिले में अब तक 6776 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 6381 हितग्राहियों ने वेंडर का चयन कर लिया है। 3255 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। 2218

लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान भी किया जा

चुका है।

383 मेगावाट क्षमता विकसित

जिले में 3255 घरेलू सोलर कनेक्शनों से लगभग 9 मेगावाट, 162 व्यावसायिक सोलर कनेक्शनों से 3.40 मेगावाट और 31 पावर प्लांटों के जरिए 383 मेगावाट क्षमता विकसित की गई है। इनमें सबसे उल्लेखनीय ढाबा स्थित मेसर्स सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 160 मेगावाट क्षमता वाला सोलर कनेक्शन है। इसे देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा कनेक्शन माना जा रहा है।

हितग्राहियों का सम्मान

जिला प्रशासन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हितग्राहियों को सम्मानित कर रहा है। इससे अन्य नागरिकों को भी सौर ऊर्जा अपनाने की प्रेरणा मिल रही है। राजनांदगांव की यह उपलब्धि हरित ऊर्जा की दिशा में देश के लिए प्रेरक उदाहरण बनकर उभरी है।

नाबालिग दुष्कर्म मामला सेटल करने के नाम पर वसूली, कांग्रेस नेता और पत्रकार गिरफ्तार

कार्रवाई

ऑनलाइन ली 1.30 लाख की रकम, पीड़िता का दादा पहले ही जेल में

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

सिलयारी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को सेटल करने के नाम पर वसूली करने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस नेता सूरज ठाकुर और पत्रकार सैफी खान को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोपी ईश्वर धृतलहरे और टाकेश्वर मानिकपुरी से ऑनलाइन मोड में रकम लेने का आरोप है।

पहले भेजे जा चुके हैं तीन आरोपी जेल

धरसीवां थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा। इससे पहले पुलिस पीड़िता के दादा और दो बिचौलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इन तीनों पर 1.30 लाख रुपये की वसूली का आरोप है।

चौकी प्रभारी हो चुके हैं निलंबित

बताया गया कि कांग्रेस नेता सूरज ठाकुर ने पीड़िता के दादा के साथ मिलकर पुलिस पर भी आरोप लगाए थे। इसके बाद सिलयारी चौकी प्रभारी जितेंद्र दुबे को नाबालिग दुष्कर्म मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

बिलासपुर में 3 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाश व्यापारी से कैश भरा बैग छीनकर फरार

बिलासपुर। व्यापार विहार थोक मंडी में गुरुवार को दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई। अंडा चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने कृषि उपज व्यापारी से 3 लाख रुपये से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए।

जांजगीर का व्यापारी बना शिकार : जांजगीर जिले के नवागढ़ निवासी व्यापारी उमेश कुमार साहू खरीदारी के लिए व्यापार विहार पहुंचे थे। वे लहसुन, मिर्च, आलू का कारोबार करते हैं। खरीदारी के बाद आगे सामान लेने जा रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने झपट्टा मारकर हाथ से बैग छीन लिया। घटना इतनी तेज हुई कि व्यापारी कुछ समझ नहीं पाए।

पहले से रख रहे थे नजर : बताया जा रहा है कि बदमाश काफी देर से व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। मौका मिलते ही वारदात कर मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार में भाग निकले। बैग में व्यापारिक लेनदेन के करीब 3 लाख रुपये नकद थे।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस : सूचना पर तारबाहर पुलिस मौके पर पहुंची। शहर और आसपास नाकेबंदी कराई गई है। घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र

की मदद से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। दिनदहाड़े हुई लूट से व्यापारियों में दहशत है। सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

बंगाल में टीएमसी दो फाड़ की कगार पर, 19 सांसदों का बागी गुट कल स्पीकर से मिलेगा

ऑपरेशन लोटस के बाद ऑपरेशन टाइगर की तैयारी, शिंदे को मिला महाराष्ट्र का टास्क

आलोक तिवारी / नईदिल्ली-कोलकाता

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रहा ह्यअसली बनाम नकलीह्ल का विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सयोनी घोष और काकोली घोष समेत टीएमसी के 19 बागी सांसदों के दस्तखत वाली सूची सामने आने के बाद पार्टी में विभाजन की आशंका गहरा गई है।

लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात

सूत्रों के मुताबिक 14 जून रविवार को बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इन 19 बागी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद यह गुट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग करेगा। साथ ही खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने का दावा पेश करेगा।

चुनाव आयोग में भी जाएगी लड़ाई

यह बागी गुट केंद्रीय चुनाव आयोग का भी रुख करेगा। गुट का आरोप है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर मनमाने फैसले ले रहे थे। इससे पहले चुनाव आयोग शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार गुट को असली पार्टी के रूप में मान्यता दे चुका है। इसी फॉर्मूले के चलते टीएमसी के बागी गुट की उम्मीदें बढ़ी हैं।

महुआ मोइत्रा का तर्क बनाम बीजेपी की रणनीति

दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद का तर्क है कि 91वें संविधान संशोधन, 2003 के बाद किसी अलग गुट को सीधे मान्यता नहीं मिल सकती। बागियों को किसी दल में विलय करना होगा। वहीं बीजेपी रणनीतिकारों का कहना है कि मूल पार्टी पर दावा ठोकने वाले फॉर्मूले में विलय की जरूरत नहीं होती। इसमें खुद को ही असली पार्टी साबित करना होता है।

राहुल के नेतृत्व को मिल रहा है बल

देश की राजनीति हर रोज बदल रही है और इस बार विपक्षी पार्टियों के भीतर का बदलाव बेहद चौंकाने वाला है। कभी कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाली तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी भी अब राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानने के लिए मजबूर नजर आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से देश की राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है।

फोन कॉल और 'दरियादिली' के सियासी मायने : हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। इस घटना की जानकारी मिलते ही राहुल गांधी ने तुरंत ममता बनर्जी को फोन मिलाया। उन्होंने न केवल अभिषेक का हाल-चाल जाना, बल्कि यह भी कहा कि अगर बंगाल में इलाज में कोई समस्या आ रही है, तो वे उन्हें तुरंत कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना (हैदराबाद) भेज सकते हैं।

हालांकि ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन इस फोन कॉल ने दोनों नेताओं के बीच जमी बर्फ को पिघला दिया है। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से 'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकजुट बैठक बुलाने का अनुरोध किया। जो ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में गठबंधन को एक भी सीट देने को राजी नहीं थीं, आज वही बार-बार इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रही हैं।

क्षेत्रीय क्षत्रपों का गिरता ग्राफ : राजनीतिक विश्लेषको के मुताबिक, पिछले दो सालों में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े क्षेत्रीय चेहरे कमजोर हुए हैं, जिसने विपक्ष की राजनीति को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। नीतीश कुमार कभी विपक्षी एकजुटता का चेहरा बनने की कोशिश में थे, लेकिन

गठबंधन का संयोजक न बनाए जाने के बाद वे वापस एनडीए का हिस्सा बन गए। हालांकि, बाद में बिहार में बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, जिससे उनका राष्ट्रीय प्रभाव कम हुआ। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी खुद भी चुनाव हार गईं और उनकी पार्टी को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी का कमल खिला, जिसने ममता के राजनीतिक रसूख को बड़ा झटका दिया।

क्षेत्रीय दलों का संकट : देश के अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी पारिवारिक कलह में टूट चुकी है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जगन रेड्डी के साथ समझौते की राह पर है, तो वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की बीमारी और एनसीपी में टूट (अजीत पवार के निधन के बाद की स्थिति) ने विपक्ष को कमजोर किया है। ओडिशा में नवीन पटनायक चुनाव हार चुके हैं और मायावती सियासी परिदृश्य से लगभग गायब हैं।

लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद विपक्ष को लगभग 10 साल बाद 'नेता प्रतिपक्ष' का पद मिला, जिसे राहुल गांधी ने स्वीकार किया। आज की तारीख में तमाम क्षेत्रीय दलों के पास कांग्रेस की छतरी के नीचे आने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। आने वाले समय में राहुल गांधी ही विपक्ष का इकलौता और सवर्मान्य चेहरा होंगे, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है।

सियासी समीकरण बदलने की तैयारी

बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक चल रही यह सियासी उठापटक मानसून सत्र में देश की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। अब निगाहें दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग पर टिकी हैं। असली और नकली की यह जंग कानूनी और सियासी दोनों मोर्चों पर लड़ी जाएगी।

क्या है 91वां संशोधन

91वें संविधान संशोधन, 2003 के तहत दलबदल कानून को सख्त किया गया था। इसमें किसी सदन के एक तिहाई सदस्यों के अलग होने पर ही विभाजन को मान्यता देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ विलय को मान्यता है। लेकिन अगर कोई गुट खुद को मूल पार्टी बताता है तो चुनाव आयोग पार्टी के संविधान, बहुमत और संगठनात्मक ढांचे के आधार पर फैसला करता है। यही फॉर्मूला शिंदे और अजित पवार के मामलों में लागू हुआ था।

अगला निशाना : उद्धव ठाकरे की शिवसेना

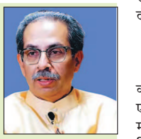

दिल्ली में हुए एनडीए कॉन्क्लेव के हवाले से सामने आया है कि बीजेपी का लक्ष्य मानसून सत्र से पहले एनडीए की लोकसभा सीटों की संख्या को दो तिहाई बहुमत यानी 360 के पार ले जाना है। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ा टास्क दिया गया है। शिंदे की नजर उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों पर है। रणनीति इनमें से 7 सांसदों को तोड़ने की है।

हालांकि उस्मानाबाद के सांसद ओम प्रकाश राजे निंबालकर के सामाजिक समीकरणों के कारण ऑपरेशन टाइगर फिलहाल अटका हुआ है। लेकिन सयोनी घोष और काकोली घोष जैसी ममता की करीबी माने जाने वाली सांसदों के पाला बदलने के बाद सियासी हलकों में कुछ भी असंभव नहीं माना जा रहा।

राजनांदगांव की महक नरवासे बनीं भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने दी बधाई, कहा बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिले की होनहार क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे को भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। महक की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इसे जिले और प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने महक नरवासे को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महक ने अपनी मेहनत, लगन और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी उपलब्धि प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है। डॉ. सिंह ने कहा कि महक ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय देकर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। उपकप्तान के रूप में उनका चयन प्रदेश के खेल जगत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महक आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाएंगी।

खेल प्रेमियों में हर्ष : महक के चयन की खबर मिलते ही खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों और स्थानीय नागरिकों ने हर्ष व्यक्त किया। खेल जगत से जुड़े लोगों ने इसे जिले में खेल प्रतिभाओं के लिए सकारात्मक संदेश बताया। लोगों का कहना है कि महक की सफलता से अन्य युवा खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

महक नरवासे लगातार अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर क्रिकेट जगत में पहचान बना रही हैं। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान बनाए जाने से उनके उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं।

महापौर मधुसूदन यादव ने दी बधाई

अमेरिका कैलिफोर्निया की छात्र-नेतृत्व वाली संस्था ने 400 से अधिक वंचित बच्चों की नि :शुल्क नेत्र जांच की

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

iCare Brighter Future Foundation, कैलिफोनिर्या, अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन, ने सफलतापूर्वक एक छात्र-नेतृत्व वाली दृष्टि देखभाल पहल आयोजित की, जिसके अंतर्गत 400 से अधिक वंचित बच्चों की नि :शुल्क नेत्र जांच और दृष्टि मूल्यांकन किया गया।

यह कार्यक्रम बच्चों को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती का समाधान करने की दिशा में कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के अनुसार, अनुमानित 9 करोड़ बच्चे विश्वभर में किसी न किसी प्रकार की दृष्टि हानि के साथ जीवन जी रहे हैं, जबकि लगभग 1.2 करोड़ बच्चों में बिना सुधारे गए अपवर्तक दोषों (Refractive Errors) के कारण दृष्टि संबंधी समस्याएँ हैं, जिन्हें अक्सर केवल एक साधारण चश्मे से ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 45 करोड़ बच्चों को विभिन्न दृष्टि संबंधी स्थितियों के उपचार की आवश्यकता है, जो सुलभ बाल नेत्र देखभाल सेवाओं की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

कई बच्चे अनपहचानी दृष्टि समस्याओं के कारण शैक्षणिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं, इसलिए समय पर

पहचान और सुधारात्मक चश्मे तक पहुँच उनकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शोध से पता चला है कि दृष्टि संबंधी समस्याएँ पढ़ने की क्षमता, कक्षा में भागीदारी, आत्मविश्वास और समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इस पहल के माध्यम से जिन बच्चों को दृष्टि सुधार की आवश्यकता पाई गई, उन्हें नि :शुल्क प्रिस्क्रिप्शन चश्मे प्रदान किए जाएंगे।

यह पहल केवल एक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम नहीं है। यह युवा नेतृत्व और सामुदायिक सेवा की शक्ति का भी उदाहरण है। छात्र स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम के आयोजन, समन्वय और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें नेतृत्व का मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुआ और साथ ही वे अपने साथी छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। कई बच्चों को यह एहसास नहीं होता कि कमजोर दृष्टि उनकी सीखने की क्षमता, कक्षा में भागीदारी और अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने की योग्यता को प्रभावित कर रही है, iCare Brighter Future Foundation के एक प्रतिनिधि ने कहा। 400 से अधिक बच्चों की जांच करके और जरूरतमंद बच्चों को चश्मे उपलब्ध कराकर, हम बेहतर शैक्षणिक परिणामों और उज्ज्वल भविष्य के अवसर पैदा करने में सहायता कर रहे हैं।

फाउंडेशन का मानना है कि स्पष्ट दृष्टि किसी भी बच्चे की शैक्षणिक सफलता का एक मूलभूत आधार है। विश्वभर में लाखों बच्चों को अभी भी बुनियादी नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुँच नहीं है, विशेष रूप से वंचित समुदायों में। एक साधारण नेत्र परीक्षण और एक जोड़ी चश्मा कक्षा में सहभागिता, आत्मविश्वास, पढ़ने की क्षमता और जीवन की समग्र गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है।

कैलिफोनिर्या स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में, iCare Brighter Future Foundation स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक सेवा पहलों के माध्यम से युवा नेताओं को सशक्त बनाने और सार्थक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम की सफलता फाउंडेशन के उस मिशन को दर्शाती है जिसमें युवा नेतृत्व को वास्तविक सामुदायिक आवश्यकताओं के व्यावहारिक समाधानों के साथ जोड़ा जाता है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ : 400 से अधिक वंचित बच्चों की दृष्टि संबंधी समस्याओं के लिए जांच की गई? भाग लेने वाले छात्रों के लिए नि :शुल्क नेत्र परीक्षण आयोजित किए गए? दृष्टि सुधार की आवश्यकता वाले बच्चों को नि :शुल्क प्रिस्क्रिप्शन चश्मे प्रदान किए गए? छात्र-नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा और नेतृत्व पहल? बिना सुधारे गए अपवर्तक दोषों से प्रभावित अनुमानित 1.2 करोड़ बच्चों की समस्या के समाधान के प्रयासों का समर्थन? बेहतर दृष्टि देखभाल के माध्यम से शैक्षणिक परिणामों में सुधार पर केंद्रित? बच्चों के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सीखने को समर्थन देने वाला सामुदायिक प्रयास है।

iCare Brighter Future Foundation कैलिफोनिर्या, अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक सेवा और युवा नेतृत्व कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। छात्रों को सार्थक पहलों का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाकर और महत्वपूर्ण सामुदायिक आवश्यकताओं का समाधान करके, फाउंडेशन बच्चों के लिए स्थायी प्रभाव और उज्ज्वल भविष्य बनाने का प्रयास करता है।

गया नगर में पानी टंकी निर्माण कार्य हुआ शुरू, रहवासियों को जल संकट से मिलेगी राहत

महिलाओं के चेहरों पर लौटी मुस्कान, वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, महापौर अलका बाघमार का किया स्वागत, नागरिकों ने जताया आभार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र के गया नगरवासियों के लिए गुरुवार का दिन खुशी और राहत लेकर आया। वर्षों से लो-प्रेशर और जल संकट की समस्या से जूझ रहे वार्ड क्रमांक-3 गया नगर के नागरिकों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई उच्च स्तरीय पानी टंकी निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया।

गया नगर स्थित कबड्डी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार की उपस्थिति में जेसीबी मशीन से खुदाई कार्य प्रारंभ कराया गया। इस अवसर पर महापौर, सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चंद्राकर, वित्त विभाग प्रभारी एवं पार्षद नरेंद्र बंजारे, जल कार्य विभाग प्रभारी एवं पार्षद श्रीमती लीना दिनेश देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बाबा धाम शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं विशेष पूजा-अचर्ना की तथा निर्माण कार्य के सफल एवं शीघ्र पूर्ण होने की कामना की।

निर्माण स्थल पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों ने फटाके फोड़कर और पुष्पमालाओं से महापौर अलका बाघमार का भव्य स्वागत किया। क्षेत्रवासियों ने वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर महापौर एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि पानी की समस्या के कारण लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई पानी टंकी बनने से अब बड़ी राहत मिलने

की उम्मीद है।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गया नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से बनी जलापूर्ति समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाएगा।

जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक-3 एवं 4 में बघेरा पानी टंकी से जलापूर्ति होने के कारण दूरी अधिक होने से लो-प्रेशर की समस्या बनी रहती थी। गर्मी के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती थी। क्षेत्र की महिलाओं और नागरिकों द्वारा लंबे समय से नई पानी टंकी की मांग की जा रही थी।

महापौर अलका बाघमार, जल कार्य विभाग प्रभारी श्रीमती लीना दिनेश देवांगन तथा पार्षद नरेंद्र बंजारे की पहल पर इस योजना को प्राथमिकता देते हुए पहली एमआईसी बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। राज्य शासन से लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से 15 लाख लीटर क्षमता की उच्च स्तरीय पानी टंकी तथा फिल्टर प्लांट से टंकी तक राइजिंग लाइन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमिपूजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सुशासन तिहार के दौरान किया गया था। अब नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्यवाही की जा रही है। कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य देवनारायण चंद्राकर, चंद्रशेखर चंद्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, पूर्व सभापति दिनेश देवांगन, पार्षद मनीष कोठारी, मंडल अध्यक्ष कमलेश फेकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, महिलाएं एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

खास खबर

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस को मिलेगा नया नेतृत्व, संदीप वोरा सहित चुनिंदा चेहरे दिल्ली रवाना

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारतीय युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों के तहत छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पात्र घोषित किए गए चुनिंदा नेताओं को दिल्ली में आयोजित होने वाले इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है।

बताया जा रहा है कि इन नामों को युवा कांग्रेस के "हाई परफॉर्मर" वर्ग में शामिल किया गया है। जिन नेताओं ने अपने पूर्व कार्यकाल में संगठन को मजबूत करने, सदस्यता अभियान, युवा मुद्दों को उठाने तथा प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ के लिए पात्र माना गया है। इसी आधार पर उनका नाम हाई परफॉर्मर सूची में शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली बुलाए गए प्रमुख नामों में संदीप वोरा भी शामिल हैं। संदीप वोरा दिल्ली में आयोजित होने वाले इंटरव्यू में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में उनके नाम को गंभीर दावेदारों में देखा जा रहा है।

गौरतलब है कि संदीप वोरा छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के सचिव एवं 2 बार के महासचिव रह चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने युवा कांग्रेस संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इनके अलावा भी कुछ अन्य नाम चयन प्रक्रिया में शामिल बताए जा रहे हैं।

स्कूल खुलने से पहले सभी तैयारियां पूरी करें, बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : कलेक्टर

जिले के शासकीय और निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

दुर्ग। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हुडको भिलाई में जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रबंधकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्कूल खुलने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए बताया कि शासकीय हाई स्कूलों में पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, जबकि सेजस एवं निजी विद्यालयों में अगले तीन-चार दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने स्कूल परिसरों की साफ-सफाई, पेयजल, वॉटर फिल्टर, शौचालय, पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जर्जर भवनों को अनुमति लेकर डिस्मेंटल करने और मरम्मत योग्य भवनों की शीघ्र मरम्मत कराने को कहा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतकर्ता बरतने की आवश्यकता बताई। उन्होंने स्कूल बसों की नियमित जांच और चालकों की मॉनिटरिंग करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा स्कूलों में नशामुक्ति अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने सभी को हेलमेट पहनने, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखने की अपील की, जिससे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

कलेक्टर सिंह ने स्कूलों में 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी एवं 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण हेतु बच्चों एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों की सहमति प्राप्त कर अधिक से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में प्रभावी है और केवल एक बार लगाया जाएगा। बैठक में विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट कार्य की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 96 प्रतिशत बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट हो चुका है। शेष बच्चों का कार्य पूरा करने के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

बाल श्रम नहीं, शिक्षा का अधिकार : विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक शिविर आयोजित

बाल श्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक व शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न करता

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के दो काउंसलर विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों एवं बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ प्रदान की।

शिविर के दौरान बच्चों को बाल श्रम की परिभाषा, उसके विभिन्न स्वरूपों तथा बाल श्रम उन्मूलन के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि बाल श्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य को प्रभावित करता है। वक्ताओं ने बच्चों को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, किशोर न्याय से संबंधित प्रावधानों तथा बाल संरक्षण के लिए बनाए गए विभिन्न भारतीय कानूनों की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम में बच्चों को शासकीय पुनर्वास योजनाओं, शिक्षा के अधिकार तथा बाल संरक्षण तंत्र के बारे में भी अवगत कराया गया। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, गुड टच एवं बैड टच की जानकारी देकर उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान उत्साहपूर्वक अनेक प्रश्न पूछे, जिनका काउंसलरों द्वारा सरल एवं सहज भाषा में उत्तर देकर समाधान किया गया।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में दुर्ग, भिलाई एवं धमधा क्षेत्र के पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने सक्रिय सहभागिता निभाई। च्स्ट टीमों ने गाँवों, शहरों एवं मोहल्लों में पहुँचकर बच्चों, युवाओं, अभिभावकों एवं आमजन को बाल श्रम के दुष्परिणामों तथा इसके विरुद्ध बने कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की।

अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। बाल श्रम करवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून में कठोर दंड एवं जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही आमजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा तथा विभिन्न कानूनी सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। बाल श्रम मुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक नागरिक इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाए और बच्चों को श्रम नहीं, बल्कि शिक्षा एवं अवसर प्रदान करे।

पुरैना में विकास कार्यों का भूमिपूजन विधायक ललित चंद्राकर ने दी सौगात

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पुरैना वार्ड क्रमांक 39 में विकास कार्यों को नई गति देते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने149.21 लाख की लागत से किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान आहाता बाउंड्रीवाल, स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक, डोमशेड, सीसी रोड एवं भवन निर्माण सहित कुल छह विकास कार्यों की सौगात क्षेत्रवासियों को मिली।

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुरैना में शुरू होने वाले इन कार्यों से क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और नागरिकों को बेहतर वातावरण मिलेगा। उन्होंने बताया कि आहाता बाउंड्रीवाल के निर्माण से सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जबकि स्ट्रीट लाइट व्यवस्था से क्षेत्र में रोशनी बढ़ेगी। वहीं सीसी रोड और पेवर ब्लॉक निर्माण से आवागमन सुगम होगा तथा डोमशेड सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोगी साबित होगा।

विधायक चंद्राकर ने कहा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड और गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है तथा डबल इंजन की सरकार में विकास की गति निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत-2047 और राज्य सरकार के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले समय में पुरैना सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में और अधिक विकास कार्य कराए जाएंगे।

कार्यक्रम में मरोदा-पुरैना मंडल अध्यक्ष राजू जंघेल, महामंत्री नरेन्द्र निर्मलकर, रिसाली नगर निगम सभापति केशव बंछोर, एमआईसी सदस्य सनीर साहू, पार्षद विक्की चंद्राकर, विधायक प्रतिनिधि गोविन्द साहू सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

पीएम स्वनिधि महोत्सव में उमड़ा उत्साह, 169 पथ विक्रेताओं ने लिया योजनाओं का लाभ

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत गुरुवार को नगर पालिक निगम दुर्ग के श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार में जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में पथ विक्रेताओं ने भाग लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त किया।

कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार एवं निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने विभिन्न विभागों और बैंकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा पथ विक्रेताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया और अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

महोत्सव में कुल 169 पथ विक्रेताओं एवं 27 बैंकों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता निभाई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत नए ऋण लाभार्थियों की पहचान के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 87 नए आवेदकों को ऋण के लिए चिन्हांकित किया गया। वहीं विभिन्न बैंकों द्वारा 45 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया तथा 54 प्रकरणों

में ऋण स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा 5 हितग्राहियों के क्रेडिट कार्ड आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए।

पथ विक्रेताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण सत्र में इंडसइंड बैंक के प्रतिनिधि दिलेश्वर निषाद ने साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल भुगतान संबंधी जानकारी दी। अग्रणी बैंक के लेखराम ने वित्तीय साक्षरता पर मार्गदर्शन देते हुए बचत, ऋण प्रबंधन और बैंकिंग सेवाओं के महत्व को समझाया। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर द्वारा 8 पथ विक्रेताओं को क्यूआर कोड बॉक्स वितरित किए गए, जिससे वे कैशलेस भुगतान प्रणाली से जुड़ सकें।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जितेंद्र नेले ने खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण दिया। वहीं शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित मेडिकल यूनिट द्वारा 46 पथ विक्रेताओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा आयुष्मान भारत योजना से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं, जिससे हितग्राहियों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सुविधाओं का लाभ मिला। महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 पथ विक्रेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के सफल क्रियान्वयन में योगदान के लिए भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक को भी सम्मानित किया गया।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने तथा डिजिटल भुगतान अपनाने का आह्वान किया।

निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा पथ विक्रेताओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। इस अवसर पर सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं निगम की टीम उपस्थित रही।

जिला चिकित्सालय दुर्ग में हृदय रोग विभाग की शुरुआत

सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. आकाश बक्शी देंगे नि:शुल्क सेवाएं

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय में हृदय रोग विभाग की शुरुआत की गई है। इस नई सुविधा के अंतर्गत सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. आकाश बक्शी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को निःशुल्क जांच एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय, जो 500 बिस्तरों की क्षमता एवं प्रतिदिन 1000 से अधिक मरीजों की सेवाओं के लिए संचालित है, अब हृदय रोग संबंधी उपचार एवं परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। चिकित्सालय में पहले से मेडिसिन, त्वचा रोग, नेत्र, कान-

नाक-गला, शल्य चिकित्सा, हड्डी रोग, मातृत्व एवं शिशु विभाग, डायलिसिस, आईसीयू, आपातकालीन सेवाएं, बर्न यूनिट तथा 500 यूनिट क्षमता वाला ब्लड बैंक संचालित है।

नव प्रारंभ हृदय रोग विभाग जिला चिकित्सालय के कक्ष क्रमांक 17 में संचालित होगा। यहां डॉ. आकाश बक्शी प्रत्येक माह के प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मरीजों का निःशुल्क परीक्षण एवं मार्गदर्शन करेंगे। इस सेवा का शुभारंभ शुक्रवार, 12 जून से किया गया।

इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ. ए.के. मिंज, जीवन दीप समिति के आजीवन सदस्य दिलीप ठाकुर एवं सतीश सुराना, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के दुर्ग संभागीय अध्यक्ष अजय नायक तथा ओम सत्यम शिक्षण एवं जन विकास समिति के अध्यक्ष सीताराम ठाकुर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय में हृदय रोग विशेषज्ञ की नियमित सेवाएं प्रारंभ होने से क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा।

शहीद दिवस के रूप में मनाई पंडित शुक्ल की पुण्यतिथि

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा आज पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्या चरण शुक्ला जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेसजनों ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके योगदान को स्मरण किया।

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि पंडित विद्या चरण शुक्ल जी का जीवन जनसेवा, विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से थे तथा उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। रेल, हवाई सेवा, सिंचाई, सड़क, दूरसंचार, उद्योग तथा दूरदर्शन जैसी सुविधाओं के विस्तार में उनका योगदान अविस्मरणीय है।

श्री बाकलीवाल ने कहा कि पंडित शुक्ल जी नौ बार सांसद चुने गए तथा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू

इंदिरा गांधी चंद्रशेखर एवं ब नरसिम्हा राव की सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वे कांग्रेस की विचारधारा के सशक्त स्तंभ थे और जनहित के मुद्दों के लिए सदैव संघर्षरत रहे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में हुए झीरम घाटी हमला में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने साहस और संघर्ष का परिचय दिया। 11 जून 2013 को उनका निधन हुआ, किंतु उनके आदर्श, विचार और विकास की सोच आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं प्रदेशवासियों को प्रेरित करती है।

इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसजनों ने पंडित विद्या चरण शुक्ल जी के बताए मार्ग पर चलने तथा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय एवं जनसेवा के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में धीरज बाकलीवाल अलताफ अहमद आनंद देव ताम्रकार प्रवक्ता सुशील भारद्वाज नासिर खोखर कल्याण सिंह ठाकुर दुष्यंत देवांगन अंश चतुर्वेदी आयुष शर्मा देव सिन्हा अनिल राव अली असगर एनी पीटर उपस्थित थे।

कला, संस्कृति और सिनेमा के संरक्षण-संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध-मुख्यमंत्री

गिधनी पाठ (छुरा) में विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये तथा धमतरी में सेन समाज भवन हेतु 10 लाख रुपये की घोषणा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में संस्कृति विभाग एवं छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं, कलाकारों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि फिल्में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज की सोच, संस्कृति और संवेदनाओं को दिशा देने वाली सशक्त विधा हैं। एक अच्छी फिल्म समाज में जागरूकता पैदा करती है और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय सिनेमा ने समय-समय पर सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों, त्याग और आत्मसम्मान की भावना को सुदृढ़ किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का गौरवशाली इतिहास रहा है। पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सार्थक संदेश दिया था। आज छालीवुड की फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ व्यावसायिक सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के विस्तार से फिल्मों की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हुई है, ऐसे में जिम्मेदार, सकारात्मक और मूल्याधारित सिनेमा को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को नई पहचान दिलाने और स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम को पुनः सक्रिय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष जनवरी में 150 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एवं कल्चरल कन्वेंशन सेंटर का भूमिपूजन किया गया है। इस परियोजना से राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, हजारों कलाकारों, तकनीशियनों एवं श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा फिल्म पर्यटन को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम एवं संस्कृति विभाग को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की कला, संस्कृति और सिनेमा को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह सराहनीय पहल है। ऐसे सम्मान समारोह कलाकारों और रचनाकारों का मनोबल बढ़ाने के साथ नई पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में 11 देशों में सम्मानित छत्तीसगढ़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म "छत्तीसगढ़ का भीम - चिंताराम" का विशेष प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दीं।

इस अवसर पर उन्होंने गरियाबंद जिले के छुरा क्षेत्र स्थित गिधनी पाठ में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये तथा धमतरी में सेन समाज भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपये की घोषणा की। इस अवसर पर सर्व सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत सेन, वरिष्ठ फिल्म निर्माता मोहन सुंदरानी, छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक, कलाकार एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खास खबर

फिल्में समाज को संदेश देने का सशक्त माध्यम- राज्यपाल रमेन डेका

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

फिल्में और डॉक्युमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक संदेश देने का एक प्रभावी साधन हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में उक्त बातें कही। यह कार्यक्रम रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

राज्यपाल ने कहा कि आदिम युग से ही मनुष्य विभिन्न माध्यमों से अपने विचार और संदेश व्यक्त करता रहा है। समय के साथ नाटक, रेडियो, टेलीविजन और अब डिजिटल माध्यमों ने इस भूमिका को और व्यापक बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले सिनेमा का मूल उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि समाज को संदेश देना और जागरूक करना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध उल्लेखनीय सफलता मिली है। फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि अब वे बस्तर की समृद्ध संस्कृति से देश और दुनिया को परिचित कराएं। इससे क्षेत्र की सकारात्मक छवि को मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल ने सद्गति, चरणदास चोर और देवदास जैसी फिल्मों और नाटकों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जागरूकता लाने वाली फिल्मों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा की लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और पर्व-त्योहारों जैसे हमारे धरोहर को स्थायी रूप से संरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। उन्होंने कलाकारों से लोककला, लोकगीत, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि मोबाइल की बढ़ती लत आज गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। बच्चे खेल के मैदानों से दूर हो रहे हैं और उनकी रचनात्मकता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कलाकारों से आग्रह किया कि वे नई पीढ़ी को कला, संगीत, नाटक और नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आगे आएं। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त डॉक्युमेंट्री फिल्मों छत्तीसगढ़ के भीम दाऊ चिंताराम, हैप्पी बथर्डे और स्क्रीन के निर्माता-निर्देशकों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन संस्कृति विभाग के संचालक संजय कन्नौजे ने दिया। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक मनोज वर्मा ने किया। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, विभिन्न डॉक्युमेंट्री फिल्मों के निर्माता-निर्देशक कलाकार एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

स्ट्रीट वेंडर्स के सपनों को मिली नई उड़ान

छत्तीसगढ़ में 1.12 लाख से अधिक वेंडर्स को मिला आर्थिक संबल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कभी सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेचने वाले, चाय-नाश्ते की छोटी दुकान चलाने वाले या फिर फुटपाथ पर रोजी-रोटी कमाने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों) के लिए पूंजी की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। बैंक ऋण तक पहुंच नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय सीमित था। लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने इन छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है।

छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से अब तक 1 लाख 12 हजार 36 से अधिक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेताओं) को 256 करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजना ने न केवल उनके कारोबार को मजबूती दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका का नया अवसर भी प्रदान किया है।

कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका पर पड़े गंभीर प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर को बिना गारंटी कायर्शील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें और उसका विस्तार कर सकें। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण में 10,000 रूपए तक का ऋण, द्वितीय चरण में 20,000 रूपए तक का ऋण तथा तृतीय चरण में 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाता है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण सहायता प्राप्त की जा सकती है। समय पर पुनर्भुगतान करने वाले हितग्राही ही अगले चरण के लिए पात्र बनते हैं।

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलता है जो सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें सब्जी एवं फल विक्रेता, चाय, नाश्ता एवं फास्ट फूड विक्रेता, पान दुकान संचालक, कपड़ा एवं रेडीमेड वस्त्र विक्रेता, जूता-चप्पल विक्रेता, किताब एवं स्टेशनरी विक्रेता, फूल एवं पूजा सामग्री विक्रेता, मोबाइल एक्सेसरीज विक्रेता, नाई, मोची, लॉन्ड्री जैसी सेवाएं देने वाले स्वरोजगारी, जैसे अनेक छोटे व्यवसाय शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और धमतरी जैसे जिलों में हजारों पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर 267.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 256.94 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जिससे 1.12 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह छोटे उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का एक व्यापक अभियान है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों में हजारों पथ विक्रेता इस योजना के सहारे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वास्तव में उन मेहनतकश हाथों को आर्थिक संबल देने का माध्यम बनी है, जो अपने परिश्रम से शहरों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं।

रायपुर की यातायात व्यवस्था में जुड़ा नया अध्याय : माइक्रो बस पायलट प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर शहर की बढ़ती यातायात समस्या के समाधान और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग और उएएह के संयुक्त तत्वावधान में माइक्रो बस पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा, परिवहन सचिव एस प्रकाश और उएएह के प्रतिनिधि सौरभ उपस्थित रहे।

पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा यह प्रोजेक्ट इस 45 दिवसीय पायलट प्रोजेक्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर की आवश्यकता को देखते हुए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल एक ट्रायल नहीं है, बल्कि एक बड़ी काययीजना की शुरुआत है। 45 दिनों के ट्रायल के बाद इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे न केवल रायपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

यातायात सुगम और पर्यावरण के अनुकूल सांसद ने कहा कि रायपुर के भारी ट्रैफिक को देखते हुए ये माइक्रो बसें अत्यंत उपयुक्त हैं। एसी सुविधाओं से लैस ये बसें न केवल नागरिकों को आरामदायक सफर देंगी, बल्कि सड़कों पर व्यक्तिगत वाहनों की संख्या को कम कर ट्रैफिक का दबाव भी घटाएंगी। इससे शहर में जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। ऑटो चालकों के लिए भी बढ़ेगा व्यवसाय ऑटो चालकों की चिंताओं पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए सांसद ने कहा कि उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सेवा के शुरू होने से लोगों का सार्वजनिक परिवहन की ओर रुझान बढ़ेगा। जब लोग अपने निजी वाहन छोड़कर सड़कों पर निकलेंगे, तो वे बसों के साथ-साथ ऑटो का भी उपयोग करेंगे, जिससे अंततः ऑटो चालकों का व्यवसाय भी बढ़ेगा और शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पहल के सफल होने की कामना की है और रायपुरवासियों से इस आधुनिक परिवहन सेवा को अपनाने की अपील की है ताकि रायपुर को एक 'सुगम और स्मार्ट शहर' बनाया जा सके।

छग दुकान व स्थापना अधिनियम नियमों में बड़ा बदलाव, 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए व्यापारियों, दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बना दिया है। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नियम 4, नियम 5 तथा प्रपत्र-2 को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। नए संशोधनों का उद्देश्य व्यवसायों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना, मानवीय हस्तक्षेप कम करना तथा ऑनलाइन शासन व्यवस्था को मजबूत करना बताया जा रहा है।

संशोधित नियम 4 के तहत अब नियोक्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज तथा ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के बाद 24 घंटे के भीतर वेब पोर्टल से श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। पहले पंजीयन प्रक्रिया में विभागीय स्तर पर अधिक समय लगता था, जब कि अब समयबद्ध सेवा का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है।

संशोधन के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित किया जाएगा। इससे कागजी कार्रवाई में कमी आएगी तथा विभागीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण होगा। नए नियमों के तहत वेब पोर्टल के माध्यम से जारी श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत पूर्णतः वैध माना जाएगा। यदि आवेदन में दी गई जानकारी, तथ्य या दस्तावेज भ्रामक, त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाए जाते हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। इससे स्व-घोषणा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने

का प्रयास किया गया है। अब प्रत्येक दुकान एवं स्थापना संचालक को प्रतिष्ठान के प्रमुख एवं स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

यदि नियोक्ता या भागीदार का नाम, पता, कमर्चारियों की संख्या, प्रतिष्ठान का पता अथवा व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रमाणपत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ई-चालान के माध्यम से करना होगा। संशोधन आवेदन प्राप्त होने के बाद नया या संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र भी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन जारी करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने पुराने प्रपत्र-2 को पूरी तरह हटाकर नया प्रपत्र लागू किया है। इसमें पहले की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारियां शामिल की गई हैं। नई जानकारी जो दर्ज करनी होगी, उसमें श्रम पहचान संख्या एवं दिनांक, प्रतिष्ठान का पूरा पता, ई-मेल एवं मोबाइल नंबर, व्यवसाय, व्यापार का स्वरूप, निजी अथवा सार्वजनिक स्थापना का विवरण, संगठन का प्रकार (प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ट्रस्ट, सहकारी संस्था आदि), ईएसआई एवं ईपीएफ पंजीयन की जानकारी, नियोक्ता एवं प्रबंधक का विवरण, मुख्यालय की जानकारी, कमर्चारियों का वर्गवार विवरण, साप्ताहिक अवकाश का उल्लेख, कर्मचारियों का विस्तृत विवरण शामिल है। राजपत्र के अनुसार पुराने नियम 4, नियम 5 और प्रपत्र-2 को यथावत संशोधित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अर्थात पुराने प्रावधान अब प्रभावी नहीं रहेंगे और उनकी जगह नए नियम लागू होंगे।

श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। ऑनलाइन पंजीयन, 24 घंटे की समय-सीमा, स्व-घोषणा आधारित प्रमाणपत्र तथा संशोधन की डिजिटल व्यवस्था से छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और सेवा प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी। विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने श्रम विभाग की सेवाओं को डिजिटल, समयबद्ध और स्व-प्रमाणन आधारित बनाकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है।

छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए बिछा रेड कारपेट, 9,580 करोड़ रुपये के मिले प्रस्ताव

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गो सुविधाओं तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योगों के लिए इसे अत्यंत अनुकूल बनाती है।

सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हाइपरनेक्स्ट डाटा सेंटर लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया। इस परियोजना से राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेगा। इस परियोजना से लगभग 250 रोजगार सृजित होंगे। फीग्रेड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट क्षेत्र में 2,912 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं निवाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर असेंबली से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव दिया। इससे राज्य में आधुनिक तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा एवं लगभग 200 रोजगार सृजित होंगे।

सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की एसजी मार्ट लिमिटेड ने 700 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 450 लोगों को रोजगार मिल सकता है। सरवणा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 528 करोड़ रूपए के निवेश से अत्याधुनिक टेक्सटाइल और परिधान निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना से लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की काबरा ड्रग्स ने 200 करोड़ रुपये तथा डेयरी क्षेत्र की दिनशॉज डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 40 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों परियोजनाओं से क्रमशः लगभग 250 और 150 रोजगार सृजित होंगे। हैदराबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने देश की कई अग्रणी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इनमें पेज इंडस्ट्रीज और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस एनर्जी, सेल्कॉन ग्रुप, मैग्नमविंग्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल रहीं। बैठकों में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और राज्य सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा स्वामी नारायण गुरुकुल संगठन के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रायपुर के टाटीबंध में 650 बिस्तरों वाले चौरिटेबल अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा की।

कार्यक्रम में सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री रितु सैन, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक एवं अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।

संपादकीय

आपदा में अवसर ढूंढ रही है कांग्रेस

पं.बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाई,वह समझ रही थी कि पार्टी का अस्तित्व उसके कारण है, वह है तो पं. बंगाल में टीएमसी है,उनके कारण ही पं.बंगाल में विधायक, सांसद चुने गए हैं।एक हार से उन्होंने पिछले 15 साल में जो बंगाल की शेरनी की तिलस्म खड़ा किया था,अपराजेय होने का तिलस्म खड़ा किया था,वह एक ही हार में टूट गया है और वह शेरनी से बिल्ली हो गई हैं।जिन कांग्रेस नेताओं से वह खुद को बड़ा नेता समझती थीं,वह कांग्रेस नेता आज उनके लिए बड़े हो गए हैं।पं.बंगाल में पीएम मोदी व भाजपा को हराने वाली ममता आज पीएम मोदी से हारने वाले नेताओं की कतार में खुद को खड़ी पा रही है और उनके साथ उनको समझौता करना पड़ रहा है।

टीएमसी के विधायकों ने पहले ही ममता से अलग होने का फैसला कर लिया है, अब सासंद भी ममता के साथ रहने को तैयार नहीं हैं।एक एक नेता टीएमसी व ममता का साथ छोड़ते जा रहे हैं। हर घटनाक्रम से ममता कमजोर से कमजोर होती जा रही हैं। पहले उनकी सरकार गई अब उनकी पार्टी भी हाथ से जाने वाली है। ऐसे में ममता बैनर्जी की सोनिया गांधी व अभिषेक बैनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी व ममता बैनर्जी व अभिषेक बैनर्जी का एक ही दुख है।उनको दुखी करने वाला एक ही शख्स है, पीएम मोदी।सोनिया गांधी का राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना पीएम मोदी के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी चुनाव के बाद चुनाव हारते जा रहे हैं। ममता बैनर्जी का सपना था कि अपनी जगह मजबूती से अभिषेक बैनर्जी को पं.बंगाल में नेता के रूप में स्थापित करना, लेकिन पीएम मोदी से चुनाव हारने के बाद अभिषेक की वही हालत हो गई है जो राहुल गांधी की है। राहुल गांधी पीएम नहीं बन पा रहे हैं और अभिषेक इस बार पं.बंगाल का सीएम बनना चाहते थे, नहीं बन सके हैं।

इस बात में दो मत नहीं है कि ममता बैनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई तो अपने दम पर पं.बंगाल में एक मुकाम हासिल किया। पं.बंगाल में उसने कांग्रेस की जगह ली और कांग्रेस को जमीन पर इतना कमजोर कर दिया कि उसके होने नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था।पं.बंगाल में कांग्रेस की आज बुरी हालत है तो वह ममता के कारण हैं क्योंकि उसने न कांग्रेस का सहयोग किया और न कांग्रेस का सहयोग लिया। वह किसी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी की पक्षधर नही थी, वह अकेले चुनाव लड़ती, जीतती थी और अकेले सत्ता का भोग करती थी। वह पंद्रह साल इसी मुगालते में रहीं कि वह अकेली है इसलिए ताकतवर हैं,सबसे शक्तिशाली हैं लेकिन आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि मैं अकेली भाजपा को हरा नहीं सकी अगर कांग्रेस को उसने मजबूत बनाए रखा होता तो कांग्रेस के साथ मिलकर वह भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकते थे।

टीएमसी और ममता की हार कांग्रेस के लिए आपदा मे अवसर जैसा है क्योंकि पं.बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करना राहुल गांधी के बूते की बात नहीं है। वह बीस साल में पं.बंगाल मे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, आगे भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि कमजोर हो गई ममता को ही यह काम दे दिया जाए जब ममता खुद उनके पास आई हैं उनकी शरण में आई हैं। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से ममता के लिए आफर है कि वह टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर दे। बदले में उसे कांग्रेस का महासचिव पद दिया जाएगा और पं.बंगाल में कांग्रेस की वही सबसे बड़ी नेता होंगी। यानी टीएमसी के पहले ममता को कांग्रेस में जो कद था उनका पं.बंगाल में वही कद होगा। उनको भाजपा से लड़ना होगा, यानी सोनिया गांधी चाहती हैं जैसे कांग्रेस के नेता अन्य राज्यों में जैसे कांग्रेस को चला रहा है, कांग्रेस के अस्तित्व को बनाए हुए है, पं.बंगाल में कांग्रेस के अस्तित्व को ममता बचाए और मजबूत करे यानी कांग्रेस को वापस सत्ता में लेकर आए।

अगर ममता कांग्रेस में शामिल होना मान लेती हैं तो इससे उनका राजनीतिक कद राहुल गांधी से छोटा हो जाएगा, वह अब तक खुद को राहुल गांधी से बेहतर नेता इसलिए कहती थी क्योंकि वह मोदी को हराने वाली थी, अब वह भी राहुल गांधी की तरह मोदी से हारने वाली नेता हो गई है और कांग्रेस में शामिल हो जाती है तो उनको राहुल गांधी के नेतृत्व का न चाहकर भी स्वीकारना होगा। सोनिया गांधी एक तरह से ममता को राहुल गांधी के रास्ते से हटाना चाहती हैं क्योंकि अभी भी वह राहुल गांधी की राह में बाधा बन सकती हैं। ममता अगर कांग्रेस में शामिल नहीं होती है तो वह दिल्ली की राजनीति करेंगी, दिल्ली की राजनीति करेंगी तो वह राहुल विपक्ष के नेता न बने या न माने जाए, इसके लिए केजरीवाल,स्टालिन,अखिलेश आदि नेताओं का उपयोग कर सकती हैं। राहुल की जगह खुद विपक्ष का नेता बनना चाहेंगी। उनकी मुश्किल यही है कि ऐसे में उनकी पार्टी के नेता ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं।

विदेश नीति के भी महारथी हैं प्रधानमंत्री मोदी!

संजय उवाच

प्रो. संजय द्विवेदी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा जाता है कि वे विदेश यात्राएं खूब करते हैं। एक जमाने में उन्हें लेकर मजाक भी चला कि कुछदिन तो गुजारिए हिंदुस्तान में। किंतु उनकी विदेश यात्राओं ने भारत के साथ दुनिया के साथ रिश्तों को सहज किया है। खासकर अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते अपने उच्चतम स्तर पर हैं। संवाद की सहजता और गतिशीलता ने भारतीय विदेश नीति को एक नए मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां औपचारिक संवाद से आगे व्यक्तिगत रिश्तों की बात भी होने लगी है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप हों, चीनी राष्ट्रपति हों या रूस के पुतिन। सबके सब मोदी का नाम लेते हैं और भारत को नजरंदाज नहीं कर सकते। इटली दौरे पर पीएम मोदी ने जियोजिर्या मेलोनी को पारले कंपनी की 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया, यह पल इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ और मेलोनी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो शेयर करके पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। जाहिर है ऐसे दृश्यों के बीच नरेंद्र मोदी ने रिश्तों का जो पुल बनाया है। उसकी चर्चा समूची दुनिया में है।

वैश्विक तनाव के बीच भारत-यूरोप संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली सहित कई यूरोपीय देशों का दौरा किया। यह यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में जंग के हालात हैं। इन तनावपूर्ण हालात में प्रधानमंत्री का उद्देश्य सिर्फ रिश्ते बनाना नहीं हैं बल्कि भारत की जरूरतों के लिए भी है। यह तो तय है प्रधानमंत्री कोई भी काम अकारण नहीं करते। कई बार उनकी दूरदृष्टि देखी गयी है। जबकि आज की राजनीति तुरंत परिणाम देने वाले संकेतों को ही समझती है। जबकि विदेशनीति में आज रोपे गए बीज कल वृक्ष बनकर परिणाम देते हैं। संवाद और सातत्य ही इसका एकमात्र हल है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा भी अनेक लक्ष्यों को साधती है। बताते है कि उनकी यह यात्रा तो काफी पहले से ही नियोजित थी जिसमें भारत-नार्डिक शिखर सम्मेलन भी शामिल था। किंतु 2025 में हुए पहलगाम हमले से सारा कुछ ठहर गया। यह यात्रा उन भारत-यूरोप संबंधों पर नए तरह से रिश्तों को पारिभाषित करना चाहती थी, क्योंकि इन दिनों वैश्विक राजनीति में विश्व शक्तियों का आचरण और व्यवहार काफी कुछ बदला हुआ है।

युद्ध में दुनिया और भारत की भूमिका

यूक्रेन युद्ध से प्रारंभ हुआ वैश्विक तनाव अब इजराइल-अमरीका और ईरान युद्ध तक जा पहुंचा है। युद्धकामी शक्तियां पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत जैसा देश जो अपनी ऊर्जा सहित तमाम जरूरतों के लिए दुनिया के तमाम देशों पर निर्भर है, वह बैठा नहीं रह सकता। साथ ही अमरीका की टैरिफ से जुड़ी मनमानियां और चीन का अड़ियल रवैया भारत को शांति से बैठने नहीं दे रहा। ऐसे में भारत के राष्ट्रध्यक्ष की चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। उन्हें न सिर्फ देश के अंतर की व्यवस्था के सामान्य रखना है बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत के हितों का ख्याल रखना है। क्योंकि दोंनो एक दूसरे से संयुक्त हैं। हम देखते हैं कि पिछले साल लागू हुआ भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता और इस साल के आखिर में संपुष्ट/हस्ताक्षरित होने वाला भारत-ईयू एफटीए सप्लाई चेनों और बाजारों में विविधता लाने की साझा इच्छा को दिखाते हैं। खास तौर पर उन नॉर्डिक देशों के साथ, जहां भारत के संग होने वाला द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर के नीचे बना हुआ है। ऐसे में भारत को इन देशों के साथ ज्यादा बेहतर रिश्ते बनाने की जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता।

आज के समय में भारत की प्राथमिकता एक ऐसी दुनिया को स्थापित करने पर जिसमें विदेशी मुद्रा और ऊर्जा संरक्षण दोनों की बचत हो सके। इन लक्ष्यों को साधे बिना किसी भी विकासशील देश के सामने गहरे संकट घिर जाएंगें। संयुक्त अरब अमीरात में दीघर्कालिक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्वों पर और नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन में हरित रणनीतिक साझेदारियों पर हुई चर्चाओं का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग को आगे ले जाना था। मोदी इन सामूहिक लक्ष्यों के साथ युद्धविहीन दुनिया का सपना देखते हैं। वे साफ कहते हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। आंतकवाद और युद्ध विहीन दुनिया उनका ही हर भारतवासी का सामूहिक स्वप्न है। क्योंकि भारत का उद्देश्य ही विश्वमंगल है और उसका ध्येय मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम् है। प्रधानमंत्री इसी भारत भाव को दुनिया के हर मंच पर स्थापित करते हुए दिखते हैं। मोदी की समूची यात्रा में यूक्रेन और ईरान संघर्षों पर स्वस्थ चर्चा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत शामिल रही। एआई गवर्नेंस और क्रिटिकल मिनरल संबंधी पहलों पर भी फोकस था। नॉर्डिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए आर्कटिक में वैज्ञानिक सहयोग और समुद्री (मैरिटाइम) सहकार पर फोकस किया। इन दौरों से कुछ खास ठोस नतीजे या वास्तविक व्यापार समझौते हासिल नहीं हुए, लेकिन दोस्ताना माहौल और मोदी को दिये गये पुरस्कारों ने ज्यादा गहरे भारत-यूरोप सहयोग की उम्मीदों का संकेत दिया। यह जुड़ाव और मजबूत होगा जब वह जून में जी-7 आउटरीच समिट के लिए फ्रांस की यात्रा करेंगे और स्लोवाकिया का द्विपक्षीय दौरा करेंगे, और इसी साल के आखिर में ब्रुसेल्स में भारत-ईयू एफटीए पर दस्तखत करेंगे।

पांच देशों की यात्रा से बने हैं रिश्ते और सरोकार

रिश्तों पर खास जोर

यह यात्रा साफ बताती है कि प्रधानमंत्री यूरोपीय देशों से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। एक शानदार लोकतंत्र भारत के लोग यूरोप के देशों से जुड़ना चाहते हैं। उनका विचार है यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूक्रेन में रुस की आक्रामता, अमरीकी-इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच चीन का आर्थिक दबाव तीन ऐसे कारण हैं जो हमें साथ होने के प्रेरित करते हैं। इसका साफ उद्देश्य है कि अंतराष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था बने और चले भी। ताकि किसी देश की तानाशाही के आधार पर चीजों को बिगाड़ा न जा सके। भारत ईएफटीए व्यापार समझौते और आगामी भारत ईयूएफटीए पर केंद्रित है। इसके साथ ही मोदी का जोर आपूर्ति श्रृखंलाओं और बाजारों के विविधीकरण पर है। ताकि हमारा व्यापार विशेष रुप से नार्डिक देशों के साथ बढ़ सके, जो अभी मात्र 20 अरब डालर से कम है। जाहिर तौर यह क्षेत्र संभावनाओं से भरा है, जहां भारत दांव लगा रहा है।

ऊर्जा जरुरतों के लिए बढ़ती साझेदारी

भारत की ऊर्जा जरूरतें इस समय एक बड़ी चुनौती हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर चर्चा हुई। भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीघर्कालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रे टेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। इसमें पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे।दोनों पक्षों ने एलपीजी पर एक अलग रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है।

संवाद से संकटों के हल तलाशने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग रहते हुए भी संकटों के हल के लिए चल रहे प्रयासों से खुद को अलग नहीं किया। वे संवाद के स्तर रूस और यूक्रेन दोनों देशों से संवाद बनाए हुए हैं। इसी तरह ईरान, इजराइल और अमरीका से भारत का संवाद निरंतर है। इन यात्राओं में प्रधानमंत्री ने एआई गवर्नेंस पर चर्चा की और खनिज पहलों पर भी संवाद किया। ओस्लो में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डेनमार्क की कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओपी, आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टुन म्योल फ्रॉस्टडॉटिर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन 2022 में कोपेनहेगन और 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित पिछले दो शिखर सम्मेलनों पर आधारित है। प्रधानमंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि वे वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल और तीव्र आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं और साझा हितों और मूल्यों पर आधारित पारस्परिक लाभ के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सहयोग करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत-नॉर्डिक संबंधों को एक विश्वसनीय हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया।प्रधानमंत्रियों ने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया और भारत-नॉर्डिक सहयोग को और अधिक विस्तारित एवं गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। नेताओं ने निर्णय लिया कि चौथे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी फिनलैंड करेगा।

सम्मान से जीवंत रिश्तों का प्रारंभ

नार्वे में उन्हें ह्यद रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉसह्नसे सम्मानित किया गया तो वहीं स्वीडन के प्रतिष्ठित ह्नरॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉसह्न से भी वे अलंकृत किए गए।यह सम्मान भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षो में व्यापार, हरित ऊर्जा, तकनीक और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी लगातार बढ़ी है। ये सूचनाएं बताती हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के मंचों पर भारत की बात सुनी जा रही है और उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। पांच देशों की उनकी यात्रा से तत्काल भले कुछ हासिल होता हुआ न दिखे, किंतु रिश्तों की महक, खुशबू और आने वाले समय के लिए कुछ तार तो जुड़े ही हैं। विदेश नीति को इस सहजता और सौजन्य से लेना ही मोदी की विरासत है।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं। पूर्व में भारतीय जनसंचार संस्थान-आईआईएमसी के महानिदेशक रह चुके हैं।)

23वां फुटबाल विश्व कप : तीसरी दुनिया की दस्तक

हरजीत सिंह

पिछले कुछ विश्व कप मुकाबलों में तीसरी दुनिया के देशों ने, जिसमें अफ्रीकी, एशियाई और मध्य व उत्तर अमेरिकी देश आते हैं, ने संघषर्शील फुटबाल खेल का प्रदर्शन किया है। फुटबाल की दुनिया में नासमझ समझे जाने वाले इन देशों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से यह जता दिया है कि वे भी अब फुटबाल जगत की श्रेष्ठ हस्तियों का मुकाबला कर सकते हैं।

आज से शुरू हो रहे तेईसवें विश्व कप फुटबाल में लेतिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले में तीसरी दुनिया के देश—मिस्र, दक्षिण कोरिया, ईरान, इराक, जापान, मोरक्को, घाना, अल्जीरिया, सेनेगल—कुल मिला कर 23 देश नजर आयेंगे। यह तय है कि विश्व फुटबाल पर लेतिन अमेरिकी (10 खिताब) और यूरोपीय देशों (12 खिताब) के वर्चस्व को अभी तो कोई खतरा नहीं है। पिछले कुछ विश्व कप मुकाबलों में खासकर 1982 से तीसरी दुनिया के देशों ने, जिसमें अफ्रीकी, एशियाई और मध्य व उत्तर अमेरिकी देश आते हैं, ने संघषर्शील फुटबाल खेल का प्रदर्शन किया है। फुटबाल की दुनिया में नासमझ समझे जाने वाले इन देशों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से यह जता दिया है कि वे भी अब फुटबाल जगत की श्रेष्ठ हस्तियों का मुकाबला कर सकते हैं।

आठवें दशक के अंत में जब फीफा अध्यक्ष हवेलेंज ने यह प्रस्ताव रखा था कि 1982 विश्व कप में 16 की बजाय 24 टीमें भाग लेंगी, तब उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस प्रस्ताव की आलोचना करने वालों में फुटबाल की श्रेष्ठ शक्तियां ही थीं, जबकि तीसरी दुनिया के देशों ने प्रस्ताव का स्वागत किया था। आलोचकों का कहना था कि इस स्वरूप के परिवर्तन से हालैंड की जगह न्यूजीलैंड, आयरलैंड की जगह कैमरून, उरुग्वे की जगह कुवैत, स्काटलैंड की जगह अल्जीरिया आदि कमजोर टीमें विश्व कप में पहुंच जायेंगी और इस से फुटबाल का स्तर गिरेगा, लेकिन इन्हीं आलोचकों को तब मुंह की खानी पड़ी, जब 1982 विश्व कप में अल्जीरिया ने दो बार की चैंपियन पश्चिम जर्मनी को 2-1 से पीट दिया।

अल्जीरिया ने पश्चिम जर्मनी को हराने के बाद चिली टीम को भी हराया, पर वह गोल औसत के आधार पर दूसरे चक्र में न पहुंच सके। इस विश्व कप में एक अन्य अफ्रीकी देश कैमरून ने अपने ग्रुप के तीनों ही मैच इटली, पौलेंड व पेरु के विरुद्ध बराबर रखे, वह भी मात्र गोल औसत के आधार पर प्रतियोगिता से बाहर हो गये।

विश्व कप फुटबाल पर एक नजर डाली जाए तो कुछ मुकाबलों को छोड़कर तीसरी दुनिया के देशों ने कई मैचों में सराहनीय खेल का प्रदर्शन दिखाया है। पहले किसी अफ्रीकी देश के रूप में मिस्र ने 1934 में विश्व कप फुटबाल में भाग लिया था। अपने एकमात्र मैच में वे हंगरी से 4-2 से हारे। तीसरी दुनिया के देशों की विश्व कप में पहली बड़ी सफलता 1966 विश्व कप में देखने को मिली, जब उत्तरी कोरिया की टीम ने दो बार की चैंपियन इटली को 1-0 से पीट डाला। कोरिया का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि उन्हें सेमीफाइनल में जाने से रोकने के लिए पुतर्गाल को पूरा जोर लगाना पड़ा क्योंकि कोरिया एक समय 3-0 से आगे थी। फाइनल स्कोर 5-3 पुतर्गाल के पक्ष में रहा।

वर्ष 1970 में अफ्रीका के छोटे से देश मोरक्को ने अपनी सुंदर फुटबाल से सब का मन मोह लिया। बुलगारिया के विरुद्ध उन्होंने मैच बराबर रखा, जबकि पश्चिम जर्मनी के विरुद्ध पहले हाफ में 1-0 से बढ़त लेने के बाद 2-1 से हारे। वर्ष 1986 विश्व कप में एक बार फिर अफ्रीका के इस देश ने सबको चकित कर दिया। वह अपने ग्रुप में इंग्लैंड, पौलेंड और पुतर्गाल जैसी सशक्त टीमों से ऊपर रहे और दूसरे चक्र में खेले। पुतर्गाल को उन्होंने 3-1 से पीटा और इंग्लैंड व पौलेंड के विरुद्ध मैच गोल-रहित रखे। दूसरे चक्र में भी इस टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, पर कड़े संघर्ष के बावजूद वह पश्चिमी जर्मनी से 1-0 से हार गये। इस प्रकार मोरक्को पहली अफ्रीकी टीम बनी जो यूरोप और अमेरिका (1966 में उत्तर कोरिया के बाद) के बाहर से केवल दूसरा राष्ट्र रहा जो दूसरे दौर में पहुंचा। इसी मोरक्को ने 2022 विश्व कप फुटबाल में कमाल कर दिया जब वह चौथे स्थान पर रहा। यह किसी भी अफ्रीकी या अरब राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ विश्व कप फिनिश रहा। अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के बाद मोरक्को ने दूसरे दौर में स्पेन को हराया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पुतर्गाल को हराया। तीसरे स्थान के लिए वह क्रोएशिया से हार गए।

कैमरून 1990 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना पर चौंकाने वाली जीत के साथ की। वे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हारे। तीसरी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन 2002 विश्व कप फुटबाल में देखने को मिला। पहले ही दिन अफ्रीकी देश सेनेगल ने गत चैंपियन फ्रांस को 1-0 से हराया। जब सेनेगल ने अतिरिक्त समय में गोल्डन गोल के साथ स्वीडन को 2-1 से हराया, तो अंतिम आठ में पहुंचने वाली केवल दूसरी अफ्रीकी टीम बन गई (1990 में कैमरून के बाद)। एक और हैरान करने वाली टीम मेजबान दक्षिण कोरिया रही। वे पोलैंड (2-0), पुतर्गाल (1-0), इटली (2-1) और स्पेन (पेनल्टी 5-3) को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे। ऐसा करने वाली पहली एशियाई टीम रही। तीसरे स्थान के लिए तुर्की ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया। वर्ष 2010 विश्व कप के राउंड 16 में, घाना अतिरिक्त समय के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को हराकर अंतिम आठ में पहुंचने वाला तीसरा अफ्रीकी देश बना (1990 में कैमरून और 2002 में सेनेगल के बाद)। 2014 में पहली बार, अफ्रीका (नाइजीरिया और अल्जीरिया) की दो टीमें दूसरे दौर में आगे बढ़ीं, एक उपलब्धि जो 2022 के टूर्नामेंट में दोहराई गई। पिछले विश्व कप में तीसरी दुनिया के चार देश—दो अफ्रीका से और दो एशिया से दूसरे दौर में रहे। सेनेगल, मोरक्को, जापान और दक्षिण कोरिया में से सिर्फ मोरक्को ही आगे बढ़कर चौथे स्थान पर रहा।

विश्व कप फुटबाल के मुकाबले में इस बार 23 देश तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 32 से 48 टीमों के स्वरूप का सबसे अधिक फायदा यूरोप को हो रहा है। साल 2022 में जब आखिरी बार 32 टीमें विश्व कप में उतरी थीं, तो यूरोप की 13 (पिछले विजेता फ्रांस सहित), लेतिन अमेरिकी की 4, मध्य व उत्तर अमेरिकी की 4, अफ्रीका की 5 और एशिया की 6 टीमों (मेजबान क़तर सहित) ने भाग लिया था। इस बार यूरोप की 16, लेतिन अमेरिकी की 6 (पिछले विजेता अर्जेंटीना सहित), मध्य व उत्तर अमेरिकी की 6 (मेजबान यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा सहित), अफ्रीका की 10, एशिया की 9 टीमें और ओशिनिया की एक टीम है।

इस बार 4 देश पहली बार भाग ले रहे हैं—जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, केप वेर्डे और कुराकाओ। कुराकाओ विश्व कप के लिए भाग करने वाला जनसंख्या (1.6 लाख) के हिसाब से सबसे छोटा देश है। मजेदार बात ये हो रही है कि विश्व कप के वार्म-अप मैचों में जहां आइवरी कोस्ट ने फ्रांस को 2-1 से और अल्जीरिया ने नीदरलैंड्स को 1-0 से हराया, जबकि इराक ने स्पेन को, घाना ने वेल्स को और कांगो ने डेनमार्क को बराबरी पर छोड़ा है। यही नहीं, तीसरी दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ी यूरोप और अमेरिकी देशों के लिए खेल रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि उनकी पहुंच अब सर्वश्रेष्ठ टीमों में है।

आय और व्यय के आंकड़े

आय कर रिटर्न्स से उभरा रुझान साफ है। भारत में प्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक से अधिक धनी वर्गों पर निर्भर होता जा रहा है। वैसे, विषमता बढ़ने की पुष्टि हवाई यात्रा संबंधी ताजा आंकड़ों से भी हुई है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दाखिल हुए आयकर रिटर्न्स से देश में बढ़ रही आर्थिक गैर-बराबरी की झलक मिली है। एक अंग्रेजी वित्तीय अखबार के विश्लेषण के मुताबिक पांच लाख रुपये तक आमदनी वाले व्यक्तियों के रिटर्न की संख्या 2024-25 की तुलना में गिर कर लगभग आधी रह गई है। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ कि गुजरे वित्त वर्ष में सरकार के आय कर दरों में बढ़ोतरी करने की वजह से बहुत से लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने की अनिवायर्ता नहीं रह गई। मगर इससे यह भी जाहिर होता है कि लोगों के क्रमिक रूप से ऊपर के आय वर्ग में शामिल होने का क्रम टूटा हुआ है।

2019-20 के बाद से 2022-25 तक पांच लाख से कम आबादी वाले वर्ग की ओर से सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल होते थे। मगर अब पांच से दस लाख रुपये के बीच की आमदनी वाले समूह ने यह स्थान हासिल कर लिया है। 2024-25 में इस आय वर्ग में चार करोड़ 75 लाख रिटर्न फाइल हुए थे, जो पिछले वर्ष पांच करोड़ 45 लाख तक पहुंच गए। रुझान साफ है। भारत में प्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक से अधिक धनी वर्गों पर निर्भर होता जा रहा है। वैसे, विषमता बढ़ने की पुष्टि हवाई यात्रा संबंधी ताजा आंकड़ों से भी हुई है।

2011-12 में हर दस लाख आबादी पर 649 परिवारों के 775 लोगों ने हवाई यात्रा की थी। तब कुल छह करोड़ 80 लाख हवाई यात्राएं हुईं। 2023-24 में हवाई यात्राओं की संख्या 15 करोड़ 37 लाख तक पहुंच गई। लेकिन ये यात्राएं हर दस लाख आबादी में 471 लोगों ने की, जो 469 परिवारों से आए।

मतलब यह कि 2011 में हवाई यात्राओं की संख्या भले कम थी, मगर आबादी के हिसाब से यात्रियों का अनुपात कहीं बड़ा था। महंगी कारों एवं अन्य उपभोक्ता चीजों की खरीदारी के आंकड़ों से भी इसी रुझान का संकेत मिलता है। इसीलिए सरकार के विषमता घटने के दावों पर यकीन करना मुश्किल होता गया है। मसलन, पारिवारिक उपभोग खर्च सर्वे रिपोर्ट-2023-24 में ऐसा दावा किया गया। जबकि आय एवं व्यय के अन्य आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं।

बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल आयोग का बड़ा एक्शन, डॉ. वणिकर्ा शर्मा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई

जोखिमपूर्ण फैक्ट्री से 9 नाबालिग मुक्त, कुल 20 बच्चों को संरक्षण, दूसरे प्रदेशों के नाबालिगों का रेस्क्यू, बाल तस्करी के एंगल से होगी जांच

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में बच्चों के संरक्षण हेतु प्रदेशभर में विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र से 9 नाबालिग बच्चों, बिलासपुर में आरपीएफ के माध्यम से 7 बच्चों तथा रायपुर जीआरपी के माध्यम से 4 बच्चों का रेस्क्यू कर कुल 20 बच्चों को संरक्षण में लिया गया।

इसी क्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वणिकर्ा शर्मा के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के उरला स्थित मारुति नंदन स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में विशेष औचक छापामार कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि लोहे की फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से गंभीर एवं जोखिमपूर्ण प्रकृति का कार्य कराया जा रहा था। मौके से 9 बच्चों को तत्काल संरक्षण में लेकर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया तथा उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ में पता चला कि रेस्क्यू किए गए बच्चे ओडिशा, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निवासी हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें एक ठेकेदार के माध्यम से रायपुर लाया गया था, जो बिहार का रहने वाला है। मामले में संबंधित ठेकेदार, बच्चों को यहां लाने वाले अन्य व्यक्तियों तथा संभावित बाल तस्करी के पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। बच्चों के परिजनों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया बच्चों के साथ क्रूरता, शोषण एवं अवैध रूप से जोखिमपूर्ण कार्य कराए जाने के तथ्य सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, 79 एवं 143 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बाल श्रम एवं संभावित बाल तस्करी से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं की भी विस्तृत जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वणिकर्ा शर्मा ने कहा कि, बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, विशेषकर तब जब उनसे जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कराया जाता है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है। बाल श्रम एवं बाल तस्करी जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध आयोग पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी संजय निराला, विपिन ठाकुर, श्रम विभाग की टीम एवं संबंधित अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति रही। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को आवश्यक संरक्षण, परामर्श, चिकित्सकीय सहायता एवं पुनर्वास की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।

खास खबर

उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर ठेकेदार को नोटिस जारी, निरीक्षण के दौरान काम की धीमी प्रगति पर जताई थी नाराजगी

नई दृष्टिबिंदु / बस्तर

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान 6 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान काम के पिछड़ने एवं लेट-लतीफी पर ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने अनुबंध के अनुसार कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। बस्तर जिले में केशलूर के पास 69 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ने निर्माण एजेंसी मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को जारी नोटिस में कहा है कि साइट उपलब्ध होने के बावजूद मैन-पॉवर, मटेरियल और मशीनरी की खराब व्यवस्था के कारण अलग-अलग चरणों में निर्माण के समयबद्ध लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका है। कार्यस्थल पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे है और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद काम की गति असंतोषजनक है। विभाग ने ठेकेदार को जारी नोटिस में कहा है कि उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री द्वारा विगत 6 जून को साइट के निरीक्षण के दौरान काम की बेहद धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता जताई गई थी। उन्होंने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर तुरंत पर्याप्त मैन-पॉवर, मशीनरी, सामग्री और अन्य जरूरी संसाधन जुटाकर काम में तेजी लाने तथा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करने सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। काम की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार नहीं पाए जाने पर विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सचिव आर. शंगीता नगरीय विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी, सोलर प्लांट का निरीक्षण

राजनांदगांव। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता ने शुक्रवार को राजनांदगांव शहर में चल रहे प्रमुख विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव और कलेक्टर जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सचिव ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजना के तहत निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही भवन निर्माण पूर्ण होने से तीन-चार माह पहले ही लाइब्रेरी और कैंटीन संचालन की तैयारियां शुरू करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने शहर के प्रमुख जलाशय रानीसागर का भी जायजा लिया और इसके सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने आसपास के दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने तथा कचरा तालाब में नहीं फेंकने की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने 18 एकड़ में विकसित एसएलआरएम सेंटर पहुंचकर स्वच्छता दीदियों से कचरा संग्रहण एवं प्रसंस्करण की जानकारी ली तथा कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

सूरजपुर में पैसा दोगुना करने के नाम पर की करोड़ों की ठगी, 8 आरोपी पकड़े गए

पीएसीएल चिटफंड घोटाले में 2 और डायरेक्टर गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / सूरजपुर

पीएसीएल चिटफंड घोटाले में सूरजपुर पुलिस ने कंपनी के दो और डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने निवेशकों को पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये जमा कराए थे। मैच्योरिटी पूरी होने पर रकम नहीं लौटाई। इस मामले में अब तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।

डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर थाना सूरजपुर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में पता चला कि पीएसीएल कंपनी के डायरेक्टर जिला जेल कवर्धा में बंद हैं। पुलिस टीम ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर आरोपी गुरजंट सिंह गिल उर्फ गुरजन सिंह, 82 वर्ष, निवासी मोहाली पंजाब और गुरूनाम सिंह, 77 वर्ष, निवासी रूपनगर पंजाब को सूरजपुर लाया।

करोड़ों की धोखाधड़ी कबूली

पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि अन्य डायरेक्टरों के साथ मिलकर निवेशकों से पैसा दोगुना करने का झांसा दिया। सूरजपुर जिले के निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की। थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 182/2016 धारा 420, 120बी भादसं, 4,5,6 ईनामी चिटफंड धन परिचालन स्किम पाबंदी अधिनियम 1978 और पीडीआई एक्ट 2005 की धारा 10 के तहत केस दर्ज है।

अब तक 8 गिरफ्तारियां

पुलिस इससे पहले कंपनी के 6 डायरेक्टर निर्मल सिंह भंगु, त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, जोगेन्दर टाईगर, गुरमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य

को गिरफ्तार कर चुकी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विमलेश दुबे, एसआई लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, एएसआई संजय सिंह और आरक्षक जयप्रकाश सिंह सक्रिय रहे।

आकाशीय बिजली गिरी, 3 मजदूरों की मौत और पांच लोग हुए गंभीर, तालाब निर्माण में लगे थे 80 ग्रामीण

भानुप्रतापपुर। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के कलगांव में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ। मनरेगा योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य में लगे ग्रामीणों पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

80 मजदूर थे मौजूद

बताया गया कि घटना के समय कार्यस्थल पर 70 से 80 ग्रामीण मौजूद थे। सुबह अचानक मौसम बदला और तेज गजर्ना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

घायलों का इलाज जारी

हादसे में घायल 5 लोगों को अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

मंत्री राजवाड़े के प्रयासों से दूरस्थ अंचलों में पेयजल संकट दूर

नई दृष्टिबिंदु / सूरजपुर

प्रदेश के दूरस्थ, पहाड़ी एवं जनजातीय अंचलों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों और निर्देशों से महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मंत्री के मार्गदर्शन में सूरजपुर जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा बंद पड़े सोलर पेयजल पंपों की मरम्मत तथा नए पंपों की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को पुनः सुचारु किया गया है।

सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड सहित विभिन्न दूरस्थ ग्रामों में तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया गया। ग्राम करौटी-ए (परसापारा), कोलुहा भाटपारा एवं बैजानपाठ में नए मोटर पंप स्थापित कर सोलर पंपों को पुनः कायर्शील बनाया गया, जिससे ग्रामीणों को नियमित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है।

इसके अलावा भैयाथान विकासखंड के दतिमा आमापारा इंद्रावास, कसकेला औरापारा तथा सूरजपुर विकासखंड के लटोरी कुशवाहापारा एवं मंजीरा फुलवारपारा में भी खराब सोलर पंपों की मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति बहाल की गई। वहीं चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के भाटपारा गांव में नया मोटर पंप स्थापित कर लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान किया गया, जिससे विशेष रूप से पंडो समुदाय के परिवारों को बड़ी राहत मिली है।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि प्रदेश के अंतिम छोर तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार निगरानी और त्वरित कार्रवाई की जा रही है, ताकि किसी भी ग्रामीण को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े।

ग्रामीणों ने पेयजल व्यवस्था बहाल होने पर राज्य सरकार, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें घर के समीप ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री का विकसित छग खाका नीति आयोग में पेश, पीएम मोदी ने की सराहना-रत्नावली कौशल

विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप देश के सामने, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का प्रतीक

नई दृष्टिबिंदु / मुंगेली

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ की पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा प्रस्तुत समग्र विकास विजन एवं बस्तर क्षेत्र हेतु घोषित जनकल्याणकारी योजनाओं की मुक्त कंठ से सराहना की है।

रत्नावली कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का यह विजन केवल विकास का रोडमैप नहीं, बल्कि आदिवासी बहुल बस्तर के सतत विकास, सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह प्रथम अवसर है जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र को विकास, शिक्षा और समृद्धि के केंद्र में रखकर नीति-निर्माण किया गया है। विकास विजन की प्रमुख उपलब्धियां।

आय क्रांति से आर्थिक आत्मनिर्भरता : बस्तर के आदिवासी परिवारों की मासिक आय को 3 वर्ष में 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने का संकल्प दूरदर्शी एवं ऐतिहासिक है। इससे न केवल घरेलू आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। महिला सशक्तिकरण की सुदृढ़ नींव आर्थिक स्वावलंबन से ही रखी जाती है।

डेयरी सिटी से महिला स्वरोजगार की नई गाथा: डेयरी सिटी की परिकल्पना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी। दूध पाय, भैंस वितरण एवं संग्रहण केंद्रों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक उद्यमिता का सशक्त मंच प्राप्त होगा। 2000 करोड़ रुपए से अधिक के मेगा प्रोजेक्ट से बस्तर की महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि उद्यमी बनकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगी।

सिंचाई क्रांति से किसान समृद्धि: 32,000 हेक्टेयर भूमि में ह्यखेत तक पानीइ पहुंचाने की घोषणा कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से फसल विविधिकरण संभव होगा, कृषि उत्पादन बहुगुणित होगा और अन्नदाता की आय में दीघर्कालिक स्थिरता आएगी। यह योजना किसान को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाएगी।

एजुकेशन सिटी से युवाओं को नई उड़ान: अबुधमाड़-जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली ह्यएजुकेशन सिटीइ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ग्रामीण युवाओं के लिए आशा की नवकिरण है। कृत्रिम मेधा (ह्व, सेमीकंडक्टर एवं रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण से बस्तर का युवा अब रोजगार का अन्वेषक नहीं, अपितु रोजगार का सृजनकर्ता बनेगा। प्रशिक्षण केंद्रों में स्थानीय भाषा एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता देना अत्यंत स्वागत योग्य कदम है।

सेवा डेरा और डिजिटल स्वास्थ्य से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच: 200 सुरक्षा शिविरों को ह्यसेवा डेराइ में रूपांतरित कर 371 केंद्र एवं राज्य योजनाओं को एकीकृत मंच पर लाना प्रशासनिक दक्षता एवं संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। 36 लाख नागरिकों का डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल निर्माण स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित एवं सुलभ बनाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं दूरस्थ अंचलों के निवासियों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा।

पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति: बस्तर में वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स एवं जंगल सफारी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय सराहनीय है। इससे स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष आर्थिक भागीदारी मिलेगी तथा बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा।

रत्नावली कौशल ने विश्वास व्यक्त किया कि इन ऐतिहासिक पहलों से बस्तर की आर्थिक तस्वीर ही नहीं बदलेगी, बल्कि सामाजिक संरचना में भी सकारात्मक रूपांतरण आएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार होगा, महिलाओं की आर्थिक भूमिका सुदृढ़ होगी तथा हिंसा से पहचान रखने वाले इस क्षेत्र की छवि विकास के आदर्श मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित होगी।

रत्नावली कौशल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विजन समावेशी विकास का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। बस्तर अब संसाधनों का भंडार मात्र नहीं रहेगा, अपितु अवसरों का संगम बनेगा। महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों को सशक्त किए बिना इस परिवर्तन को पूणर्ता प्राप्त नहीं हो सकती। रत्नावली कौशल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घोषित इन विकास प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विभा अवस्थी के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर महिलाओं के साथ मिलकर इन योजनाओं के त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता निभाएगा। उन्होंने समस्त जनता से इन जनकल्याणकारी पहलों में सहयोगी बनने की अपील की।

स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं की लूट का आरोप, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर सहित प्रदेशभर के बिजली उपभोक्ताओं को दिए जा रहे रीडिंग बिल और भुगतान बिल की राशि में भारी अंतर के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) से मुलाकात की। इस दौरान एमडी ने स्वीकार किया कि बिजली बिल गड़बड़ी से संबंधित 2700 प्रकरण उनके संज्ञान में आए हैं।

बिल में अंतर गंभीर समस्या

विकास उपाध्याय ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि जब राजधानी रायपुर में यह दशा है, तो रायपुर सहित पूरे प्रदेश में लाखों उपभोक्ता इस गड़बड़ी के शिकार हुए होंगे। उपाध्याय ने बताया कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम जनता महंगाई से जूझ रही है और ऐसे में विद्युत विभाग उनकी परेशानी और बढ़ा रहा है।

उपाध्याय ने कहा कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल दिया जा रहा है, उसमें भारी अंतर पाया गया है और इसके लिए विद्युत विभाग जिम्मेदार है। बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता को स्मार्ट तरीके से लूट रही है। आज वे स्वयं बिजली बिल में आ रही त्रुटियों को लेकर दजर्नों से अधिक उदाहरण लेकर पहुंचे थे, जहां सीएसपीडीसीएल के एमडी के संज्ञान में 2700 प्रकरण सामने आने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की।

स्मार्ट मीटर बंद करने की मांग

उपाध्याय ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से एक नहीं, बल्कि कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में गड़बड़ी सामने आ रही है, तो

विभाग को तत्काल स्मार्ट मीटर बंद कर देना चाहिए। क्योंकि न जाने प्रदेश के कितने उपभोक्ताओं को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। कई उपभोक्ताओं के ऑनलाइन ऑटो-पे सिस्टम सेट होते हैं, उन्हें तो यह भी मालूम नहीं होता कि बिजली बिल कितना आया है और कितना भुगतान हो रहा है। अब यदि उनका गड़बड़ी वाला बिल ऑटो-पे हो जाए, तो क्या विभाग उन्हें उनकी राशि वापस करेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि छत्तीसगढ़ में लगाए गए स्मार्ट मीटर के कारण यह समस्या आ रही है। जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता पहले से ही बिजली की महंगी दरों, स्मार्ट मीटर के कारण आने वाले अनाप-शनाप बिजली बिल, लो वोल्टेज और बिजली कटौती से हलाकान हैं। अब बिजली कंपनी दो तरह के बिल देकर उपभोक्ताओं को गुमराह कर लूट रही है

उन्होंने कहा कि पहले बिजली बिल हाफ योजना के तहत 400 यूनिट तक मिलने वाली छूट को समाप्त किया गया और अब इस महंगाई के दौर में उपभोक्ता दोगुना बिल का भुगतान कहां से करेंगे। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं की इस गंभीर समस्या पर भी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि ऊर्जा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है।

आंदोलन की दी चेतावनी

विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही की जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द प्रदेशभर से स्मार्ट मीटर हटाए जाएं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी ऊर्जा विभाग के कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी।

सीएसपीडीसीएल के एमडी से मुलाकात के दौरान विकास उपाध्याय के साथ कन्हैया अग्रवाल, दीपक मिश्रा, सुमित दास, रवि थॉमस, उत्तम साहू, राजेश पाल, अन्नू राम साहू, शिव श्याम शुक्ला, चिंता राम साहू, संदीप शर्मा, विकास अग्रवाल, संदीप सिरमौर, घनश्याम ओझा सहित अन्य लोग विद्युत विभाग कार्यालय में उपस्थित थे।

शिल्पा शिंदे की आलोचना पर हिना खान ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

'भाबीजी घर पर हैं' के निर्माता पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप के खुलासे के बाद शिल्पा शिंदा सुर्खियों में हैं। वहीं शिल्पा शिंदे पर जुबानी हमला करने के बाद हिना खान भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। हिना ने शिल्पा शिंदे की आलोचना की थी। इसके बाद हिना को लोगों ने निशाने पर लिया था। अब हिना खान ने आलोचकों को जवाब दिया है।

समय के साथ हम सभी बदलते हैं

हिना खान ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों के लिए नोट साझा किया है। ट्रोलिंग के बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स के लिए एक संदेश साझा किया, इसमें उन्होंने नफरत की जगह दयालुता को चुनने की अपील की। हिना ने लिखा, 'हम सभी गलतियां करते हैं और समय के साथ हम सभी बदलते हैं। मैंने यहां-वहां कुछ ट्वीट पढ़े, मैंने हमेशा नफरत के बजाय दयालुता, प्यार और ह्युमिनिटी को चुना है। अगर आप मेरे फैन हैं, तो मैं आपसे भी इसी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ व्यवहार करने की अपील करती हूं।'

अपनी बात मनवाने के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए

अभिनेत्री ने अपने फॉलोअर्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरों के प्रति नफरत और कठोर व्यवहार किए बिना हमें अपनी बात मनवाने के लिए इतना नीचा नहीं गिरना चाहिए। हम अमानवीय या नफरत भरे हुए बिना भी ऐसा कर सकते हैं। हम हमेशा शालीनता से अपनी बात रख सकते हैं और फिर भी प्रभावी हो सकते हैं। करुणा और प्रेम हमारी ताकत होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते और उन लोगों की तरह व्यवहार करते हैं जो बेकार में नफरत फैलाते हैं और ट्रोल करते हैं, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, चाहे आप मेरे फैन ही क्यों न हों। मैं सिर्फ अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए पॉजिटिविटी और शांति चाहती हूं। आप सभी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं।'

शिल्पा शिंदे ने किया था खुलासा

हाल ही में शिल्पा शिंद ने एक पॉडकास्ट में ये स्वीकार किया था कि उन्होंने एक दशक पहले 'भाबीजी घर पर हैं' के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराया था। शिंदे ने दावा किया कि उस समय वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थीं और आरोप लगाना उनके लिए आखिरी विकल्प था। अभिनेत्री ने यह भी स्वीकार किया कि मामला समझौते से समाप्त हुआ और उन्हें उनकी बकाया राशि मिल गई।

काफी सोचकर प्रोजेक्ट चुनती हैं शिल्पा शेट्टी

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपने फिल्मी फैसलों को लेकर काफी साफ और सख्त नजर आ रही हैं। ओटीटी के बढ़ते दौर के बीच उन्होंने खुलकर बताया कि अब वो हर प्रोजेक्ट नहीं करतीं, बल्कि बहुत सोच-समझकर चुनती हैं।

काम में कोई 'कंप्रोमाइज' नहीं करना चाहती

इंटरव्यू में शिल्पा ने साफ शब्दों में कहा कि अब वो अपने काम में कोई 'कंप्रोमाइज' नहीं करना चाहतीं। उनका मानना है कि इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद अब वही करना चाहिए जो दिल से सही लगे और स्क्रीन पर दिखने का कोई मजबूत कारण हो।

थिएटर फिल्म करना चाहती हैं शिल्पा

उन्होंने यह भी माना कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है। कई मेकर्स अब थिएटर के बजाय ओटीटी को सुरक्षित विकल्प मानते हैं, क्योंकि वहां रिस्क कम होता है। लेकिन शिल्पा का नजरिया थोड़ा अलग है। वो अब ऐसी फिल्म करना चाहती हैं, जो थिएटर्स में रिलीज हो। उन्होंने कहा, 'मेरे बच्चों ने मुझे थिएटर्स में नहीं देखा है। इसलिए मैं एक थिएटर फिल्म करना चाहती हूं। मेरे बेटे ने 2023 में सुखी देखी थी, लेकिन वो प्रीव्यू थिएटर में थी। मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसी फिल्म मिले, जैसी हम पहले बनाया करते थे।

काफी सोचकर प्रोजेक्ट चुनती हैं शिल्पा

शिल्पा ने बताया कि उन्होंने कई बड़ी फिल्मों को भी मना किया है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा उनके लिए पैसा या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि काम की क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है।

शिल्पा शेट्टी का वर्कफ्रंट

शिल्पा शेट्टी ने इंडस्ट्री में खूब पहचान बनाई है। वे आज 51 वर्ष की हो गई हैं। अपनी फिटनेस के लिए भी वे खूब जानी जाती हैं। शिल्पा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' होस्ट करती दिखेंगी। यह 12 जून 2026 से जी5 पर स्ट्रीम होगा।

'कॉकटेल 2' के लिए शाहिद कपूर ने ली रश्मिका मंदाना से तीन गुना ज्यादा फीस?

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की अदाकारी वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। अब सबकी नजरें फिल्म के बजट और इसकी स्टार कास्ट की फीस पर टिकी हैं। खबरों के मुताबिक, शाहिद कपूर इस फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने रश्मिका मंदाना से लगभग तीन गुना और कृति सेनन की फीस से लगभग दो गुना ज्यादा पैसे लिए हैं।

शाहिद कपूर ने लिए ज्यादा पैसे

'कॉकटेल 2' के मुख्य कलाकारों की फीस पर कुल 35 करोड़ रुपये खर्च किए गए। शाहिद कपूर ने इसके लिए 21 करोड़ रुपये लिए। जबकि कृति सेनन को 8 करोड़ रुपये और रश्मिका मंदाना को 6 करोड़ रुपये मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कॉकटेल 2' को 150 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है। इसमें से 35 करोड़ रुपये मुख्य कलाकारों की फीस के लिए रखे गए थे, जबकि लगभग 20 करोड़ रुपये फिल्म के प्रिंट और एडवरटाइजिंग कैंपेन पर खर्च किए गए। बाकी बचे 95 करोड़ रुपये फिल्म के प्रोडक्शन और सपोर्टिंग कास्ट की फीस में खर्च हुए। 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया कर रहे हैं। उन्होंने ही 2012 की रोमांटिक कॉमेडी 'कॉकटेल' का भी निर्देशन किया था। इसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी थे। 'कॉकटेल 2' को मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान प्रोड्यूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह सीक्वल नए किरदारों के साथ एक नई कहानी पेश करेगा।

'टीवी एक्ट्रेस' का टैग कई कलाकारों का पीछा नहीं छोड़ता

टेलीविजन से दूसरे माध्यमों की ओर कदम बढ़ाने वाले कलाकारों के लिए पहले से बनी धारणाओं को तोड़ना अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाल ही में हेली शाह ने टीवी के बाद टाइपकास्टिंग का सामना करने और किस तरह वह अब लोकप्रियता से ज्यादा सार्थक काम पर ध्यान दे रही हैं, इस बारे में खुलकर बात की। टेलीविजन के जरिए मजबूत फैन फॉलोइंग बनाने वाली हेली मानती हैं कि नए फॉर्मेट्स में काम करने के बाद भी 'टीवी एक्ट्रेस' का टैग कई कलाकारों का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन एक सच यह भी है कि सही मौके और लगातार अच्छे प्रदर्शन से, धीरे-धीरे आप लोगों की सोच बदल सकते हैं। अपने सफर के बारे में बात करते हुए हेली कहती हैं, 'मैं कई सालों तक टेलीविजन का हिस्सा रही हूं और इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। यह मेरा कम्फर्ट ज़ोन रहा है। लेकिन मैं नए अवसरों को भी तलाशना चाहती हूं, क्योंकि अक्सर मुझे सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस के रूप में देखा गया है। 'गुल्लक' जैसी शानदार कास्ट के साथ काम करना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा। मैं हमेशा से टीवीएफ के साथ काम करना चाहती थी और 'गुल्लक' के जरिए मेरा ओटीटी डेब्यू होना इसे और भी खास बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि शो की सादगी और वास्तविकता आज भी बरकरार है, और दर्शक हर सीजन से उसी तरह जुड़ाव महसूस करते हैं। 'उन्होंने आगे कहा, 'फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ अच्छा काम करने पर है। मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहती, जहां बिना किसी वजह के सिर्फ दिखने के लिए मैं इवेंट्स में जाऊं। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से जानें और पसंद करें।' गौरतलब है कि 'गुल्लक' हेली शाह के करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो रहा है। वह इसे अपने रचनात्मक दायरे को बढ़ाने और एक कलाकार के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने की दिशा में अहम कदम मानती हैं। दर्शकों का लगातार मिल रहा प्यार इस बात का संकेत है कि इंडस्ट्री में अब कलाकारों की पहचान सिर्फ टैग्स से नहीं, बल्कि उनके काम और प्रतिभा से तय होने लगी है।

नागार्जुन एक बार फिर संभालेंगे 'बिग बॉस तेलुगु' की कमान

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन एक बार फिर से 'बिग बॉस तेलुगु' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस बार नागार्जुन 'बिग बॉस तेलुगु' के नए सीजन 10 को होस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस शो का फैंस को काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इस नए सीजन को एक इंडिया कंपनी बना रही है। मेकर्स ने वादा किया है कि इस बार का गेम पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और अलग होने वाला है। शो के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नागार्जुन का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अपने पसंदीदा हीरो नागार्जुन को देखकर फैंस बेहद खुश हैं और साथ ही शो को लेकर उत्साहित भी हैं।

कैसा होगा 'बिग बॉस तेलुगु सीजन 10

इस वीडियो के साथ मेकर्स ने लिखा, 'पेश है 'बिग बॉस तेलुगु 10'। इस बार आप बिग बॉस का 'दशावतारम' देखेंगे। खेल बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं और इस बार इतिहास रचा जाएगा।'

कौन बना रहा है यह शो?

इस मशहूर शो को 'एंडेमोल शाइन इंडिया' कंपनी बना रही है, जिसके सीईओ दीपक धर हैं। यह कंपनी मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ी है और इससे पहले भी कई सुपरहिट वेब सीरीज और शो बना चुकी है। इस लिस्ट में 'द नाइट मैनेजर', 'द ट्रायल', 'कॉल माई एजेंट' और भी कई सीरीज और फिल्में शामिल हैं।

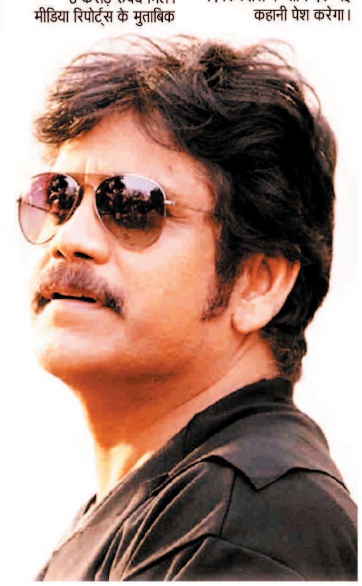

समय के साथ सिनेमा में बदलाव जरूरी, तभी दर्शकों से जुड़ी रहेंगी फिल्में

फिल्मों की दुनिया लगातार बदल रही है। दर्शक ऐसी कहानियां देखना चाहता है, जिनसे वह खुद को जोड़ सके और जिनमें उसे अपने जीवन की झलक दिखाई दे। इसी विषय पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि फिल्मों को समाज के साथ-साथ खुद को भी बदलना होगा। अगर सिनेमा समय की मांग को नहीं समझेगा, तो दर्शकों से उसका रिश्ता कमजोर हो सकता है। इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत से पूछा गया कि क्या बड़े कलाकारों की भारी फीस फिल्मों को नुकसान पहुंचाने का कारण बनती है। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ''जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, तब उसके हर खर्च पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। लोग यह देखने लगते हैं कि पैसा कहां और कितना खर्च किया गया। ऐसे समय में कलाकारों की फीस से लेकर फिल्म निर्माण के हर हिस्से पर चर्चा होती है।'' उन्होंने कहा, ''अगर किसी घर की आमदनी कम हो जाए, तो परिवार अपने खर्चों को भी कम करने की कोशिश करता है। लोग सोच-समझकर पैसा खर्च करते हैं और गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाते हैं। ठीक इसी तरह जब फिल्मों की कमाई कम होती है, तो इंडस्ट्री भी अपने खर्चों का हिसाब-किताब देखने लगती है। ऐसे में कलाकारों की फीस पर सवाल उठना स्वाभाविक बात है।''

कंगना ने आगे कहा, ''यह सिर्फ फीस का मामला नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि फिल्में समय के साथ बदलें। समाज तेजी से बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और मनोरंजन देखने का तरीका भी बदल चुका है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को भी नई पीढ़ी और नए दर्शकों की पसंद को समझना होगा। अगर फिल्में खुद को लगातार बेहतर और प्रासंगिक बनाती रहेंगी, तभी वे दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगी।'' कंगना की को-स्टार स्मिता तांबे ने भी इसी विषय पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ''हर इंसान किसी कहानी में अपने जीवन का कोई न कोई हिस्सा देखना चाहता है। दर्शक तब ज्यादा प्रभावित होते हैं, जब उन्हें लगता है कि फिल्म की कहानी या किरदार उनके जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। यही जुड़ाव किसी फिल्म को खास बनाता है।'' स्मिता ने कहा, ''हमारी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की कहानी आम लोगों से जुड़ी हुई है। इसमें ऐसी महिलाओं, मांओं, नर्सों और कामकाजी लोगों की भावनाओं और संघर्षों को दिखाया गया है, जिनसे देश का एक बड़ा वर्ग खुद को जोड़ सकता है। जब दर्शक खुद को किसी कहानी में देखेंगे, तभी वे उस फिल्म से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे।''

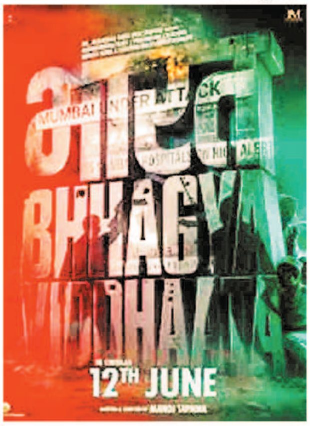

अवैध शराब के बिक्री पर रोक लगाने की मांग, महिलाओं ने एसपी से की मुलाकात

अवैध शराब बिक्री होने से लगातार क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिले के ग्राम गठुला के महिलाओं ने बड़ी संख्या में अवैध शराब के कारोबार को बंद किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा हैं,ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि अवैध शराब बिक्री होने से लगातार क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता हैं,मोहल्ले के युवा नशे की लत में आगे बढ़ रहे हैं,जिस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया हैं।

बड़ी संख्या में महिलाएं आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची ग्राम गठुला की महिलाओं का कहना है कि पिछले कुछ समय से गांव में अवैध शराब का कारोबार खुले आम चल रहा हैं,गांव के मुख्य चौक चौराहों में शराब बेची जा रही हैं,जिसके कारण मोहल्ले के युवाओं में नशे की लत शराब पीकर गाली-गलौज और मारपीट होने से महिलाओं और बच्चों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा हैं,रात के समय में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता हैं,कई पारिवारिक और आर्थिक सामाजिक समस्याएं भी शराब के कारण महिलाओं को हो रही हैं,जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने मुलाकात की और अवैध शराब के कारोबार को बंद किए जाने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया हैं।

छत्तीसगढ़ शिवसेना ने खाद एवं बीज उपलब्ध कराने बेमेतरा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा

बेमेतरा। शासकीय सोसाइटीयों में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने तहसील ऑफिस में एसडीएम बेमेतरा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, उन्होंने जिला कलेक्टर से निवेदन किया कि किसानों द्वारा बारिश पूर्व खेती कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, अब जून माह में बुवाई कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा ,किसानो की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासकीय सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, साथ ही निजी खाद विक्रेताओं को भी निर्देशित किया जाए कि वह अपनी दुकानों के बाहर सूचना पटल पर अंकित करें कि जिसमें यह उल्लेखित हो कि शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद यदि बेची जा रही हो तो किसान संबंधित नंबर पर शिकायत दर्ज कर सके। आवेदन में उन्होंने लिखा कि पिछले वर्ष निजी व्यापारियों द्वारा खाद को निर्धारित मूल्य से 2 ,3 गुना अधिक कीमत पर बेचा गया था, जिससे किसानों को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा था, किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने मांग को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। एक रैली के रूप में शिव सेना के लोग तहसील ऑफिस पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसान सेना प्रदेश अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष शिवा केसरवानी, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश वर्मा, शिवसेना प्रदेश सचिव ईश्वर प्रसाद निषाद, शिवसेना प्रदेश सचिव कमल सोनी, दुर्ग संभाग कार्यकारिणी सदस्य मनीष वर्मा, और बड़ी संख्या में शिवसेना के सदस्य उपस्थित रहे।

खास खबर

बच्चों की नेत्र जांच, मोतियाबिंद नियंत्रण व नेत्रदान जागरूकता पर दिया विशेष जोर

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में संचालित गतिविधियों की समीक्षा हेतु 4 जून को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बेमेतरा के प्रशिक्षण कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के मार्गदर्शन तथा जिला नोडल अधिकारी (अंधत्व) डॉ. बीएल राज के निर्देशन में संपन्न हुई। बैठक में जिले के समस्त नेत्र सहायक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान मोतियाबिंद से प्रभावित मरीजों की पहचान एवं उपचार, विटामिन-ए की कमी से होने वाली रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनेस), आंखों में धुंधलापन, अत्यधिक आंसू आना तथा अन्य नेत्र रोगों से संबंधित मरीजों की जांच एवं सूची तैयार करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में आंगनबाड़ी एवं स्कूली बच्चों की नियमित नेत्र जांच पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान एवं उपचार से उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए विद्यालय एवं आंगनबाड़ी स्तर पर व्यापक जांच अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में वार्षिक कार्ययोजना, जिला चिकित्सालय में मोतियाबिंद ऑपरेशन की कार्ययोजना, नेत्र रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने तथा जनजागरूकता गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। साथ ही नेत्रदान एवं देहदान जैसे मानवता के महान कार्यों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में जिला सहायक नोडल अधिकारी विद्यासागर रात्रे सहित जिले के सभी नेत्र सहायक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आमजन से नेत्रदान एवं देहदान के लिए आगे आने तथा समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की गई, ताकि जरूरतमंद लोगों को नई रोशनी और जीवनोपयोगी सहायता मिल सके।

उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, साहू कृषि केन्द्र का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित

बेमेतरा। किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी, डायवर्सन, जमाखोरी, अधिक मूल्य पर विक्रय, अमानक एवं नकली उर्वरकों के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार निरीक्षण एवं निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा 06 जून 2026 को विकासखंड बेमेतरा अंतर्गत ग्राम जेवरी स्थित मेसर्स साहू कृषि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रतिष्ठान की ओर से प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किए जाने पर उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके पश्चात उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि डॉ. श्याम लाल द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान के उर्वरक प्राधिकार पत्र के निलंबन की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप संचालक कृषि, बेमेतरा मोरध्वज डड़सेना द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 31(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स साहू कृषि केन्द्र, ग्राम जेवरी, विकासखंड बेमेतरा के उर्वरक प्राधिकार पत्र को 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा उर्वरकों के भंडारण एवं विक्रय से संबंधित किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा तथा उर्वरकों के वितरण व्यवस्था में पारदशिर्ता बनाए रखने के लिए जिले में निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

शासन की राशि का सदुपयोग करते हुए समय पर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें : आर संगीता

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आर शंगीता ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगरीय निकायों अंतर्गत शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्टर जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे।

सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आर शंगीता कहा कि नगरीय निकाय किसी भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। शहरों में विभिन्न तरह की सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध होती है। जिसके दृष्टिगत नगरीय प्रशासन को बेहतर बनाना और शासन की योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन कराना अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय अंतर्गत विभिन्न वार्डों के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि सभी नोडल अधिकारी समग्र दृष्टिकोण से अपने संबंधित वार्ड एवं क्षेत्रों के संबंध में पूरी जानकारी रखेंगे एवं नियमित मानिटरिंग करेंगे। वे अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का चिन्हांकन, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, स्वच्छता एवं अन्य जानकारी से लैस रहेंगे।

उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत की गई। शासन की राशि का सदुपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर कार्य पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने नगर निगम आयुक्त एवं सीएमओ सहित सभी अधिकारियों को सक्रियता, ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी वार्डों में जाएं व जमीन स्तर पर निरीक्षण एवं सर्वे करें तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। आपसी समन्वय एवं सहयोग से सभी टीम वर्क में शहर के विकास एवं स्वच्छता के लिए कार्य करें।

सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आर शंगीता ने कहा कि बारिश के दिनों में ऐसे स्थान जहां जल भराव की स्थिति बन सकती है, उसका चिन्हांकन करते हुए बारिश के पहले सभी नालियों के साफ-सफाई करवाएं। उन्होंने कहा कि बारिश

के मौसम में पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दरों की स्वीकृति समय पर होनी चाहिए। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एएचपी अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आवासों के आधिपत्य एवं हितग्राहियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा जियो टैंगिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों के छत, प्लिंथ, फाउंडेशन का कार्य बारिश के पहले पूर्ण करने कहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों के मकान स्वीकृति के सत्यापन का कार्य भी शीघ्र करने कहा। सचिव आर शंगीता ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्राथमिकता से शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने कहा। अमृत मिशन 2.0 के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल का भुगतान एवं अन्य कार्यों के लिए नगर पालिक निगम का अपने आय का स्रोत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मियों को संवदेनशीलतापूर्वक समय पर वेतन देना सुनिश्चित करें। सभी सीएमओ समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और जनहित के लिए कार्य करें।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिले में नगर पालिक निगम के आय बढ़ाने के लिए शासकीय भूमि पर कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में कमी लाने के लिए अधोसंरचना अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़वा दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिले में उद्यानों के मरम्मत के लिए सीएसआर के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने नगर निगम अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी।

निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नगर निगम अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई का कार्य जारी है। वही बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए नाले की सफाई भी की जा रही है। उन्होंने जल प्रबंधन, एसआरएलएम, अमृत मिशन, निर्माणाधीन कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सीसी रोड निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्य, नालंदा परिषद, बारिश के पहले सफाई कार्य, स्वीकृत कार्य, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर संचालक नगरीय प्रशासन आर एक्का, सीईओ जिला पंचायत सुरूचि सिंह, सीईओ राज्य शहरी विकास प्राधिकरण शशांक पाण्डे, उप कार्यपालन अधिकारी सचित साहू व सुनील अग्रहरि, संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग जय प्रकाश साहू सहित नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, नोडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भिलोनी साप्ताहिक बाजार में गुपचुप खाने से 21 बच्चे हुए बीमार, समय पर इलाज से बड़ा टला हादसा

बच्चों की हालत अब सामान्य, अधिकांश बच्चे उपचार के बाद अपने घर लौटे

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

नवागढ़ क्षेत्र के मारो के निकट ग्राम भिलोनी में साप्ताहिक बाजार में गुपचुप खाने के बाद 21 बच्चे अचानक उल्टी-दस्त की चपेट में आ गए। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सभी को पड़ोसी जिला मुंगेली के सरगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है और अधिकांश बच्चे उपचार के बाद अपने घर लौट चुके हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और ग्राम भिलोनी में विशेष निगरानी व उपचार शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य अमला रातभर गांव में मौजूद रहा तथा प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों की लगातार निगरानी करता रहा।बीएमओ डॉ.एम रजा ने बताया कि स्थानीय बाजार में गुपचुप खाने के बाद 21 बच्चे प्रभावित हुए थे। सभी बच्चों का समय पर उपचार किया गया और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम भिलोनी में सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया है।वतर्मान में कोई नया प्रभावित मरीज नहीं मिला है।

वहीं, दूसरी ओर इस घटना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मारो की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल में एक भी नियमित डॉक्टर पदस्थ नहीं है, जिसके कारण आपात स्थिति में मरीजों को दूसरे जिले के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। विभाग द्वारा प्रभारी चिकित्सक की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के चलते अस्पताल स्वयं बदहाल स्थिति में है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता अभियान

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा जिले के विभिन्न औद्योगिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों एवं श्रमिकों को बाल श्रम उन्मूलन तथा बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा संचालित स्टेट प्लान ऑफ एक्शन कैलेंडर-2026 के तहत यह कार्यक्रम अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सरोज नन्द दास के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

की सचिव श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव के निर्देशन में आयोजित किया गया।

अभियान के अंतर्गत सिन्हा स्टील ट्रेडर्स, वर्मा बॉडी एंड रिपेयरिंग वर्कशॉप, यस राइस मिल बेमेतरा, नवनिर्मित कार गैरेज गुनरबोड़, नांदघाट स्थित ईंट भट्ठा, नवागढ़ एवं परपोड़ी बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर लगाए गए। शिविरों में अधिकार मित्रों ने उपस्थित नागरिकों एवं श्रमिकों को बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

कार्यक्रम में बताया गया कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्त कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनके अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। आमजन से बाल श्रम का बहिष्कार करने और कहीं भी बाल मजदूरी दिखाई देने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचना देने की अपील की गई।

शिविरों में नालसा की विभिन्न योजनाओं, टोल फ्री नंबर 15100, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पॉक्सो अधिनियम 2012, हिट एंड रन मुआवजा योजना 2022, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र धरमू बारले, पंकज घृतलहरे, संजीव शर्मा, तरुण आनंद, टुवेन्द्र वर्मा, पवन साहू, देवेन्द्र यादव, नागेश सिन्हा एवं स्वाति कुंजाम सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अभियान के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

नक्सल पीड़ित परिवारों के लंबित प्रकरणों का त्वरित करें निराकरण - कलेक्टर

स्वीकृत सहायता राशि भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति व शासन की योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने कलेक्टर ने ली बैठक

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में गतदिवस जिला स्तरीय पुर्नवास समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रदान की जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति, केंद्रीय सहायता राशि तथा अन्य लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देव चरण पटेल, उप पुलिस अधीक्षक ताजेश्वर दीवान,द्वितीय कमान आईटीबीपी शरत कुमार त्रिपाठी सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नक्सल पीड़ित परिवारों से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत हो चुकी है, उनका भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए। वहीं अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूर्ण कर

पात्र आश्रितों को लाभ दिलाया जाए। बैठक में नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रित सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने अपने लंबित प्रकरणों एवं समस्याओं से समिति को अवगत कराया। कलेक्टर ने सभी मामलों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें तथा लंबित मामलों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी विभिन्न प्रकरणों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।

15 जून से जिले में चलेगा सघन कुष्ठ जांच खोज अभियान

कुष्ठ रोग मुक्त समाज के निर्माण तथा छिपे हुए कुष्ठ रोगियों की समय पर पहचान के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक सघन कुष्ठ जाँच खोज अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय खोब्रागड़े के मार्गदर्शन तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक राकेश वर्मा के नेतृत्व में जिले के सभी विकासखंडों में चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रशिक्षित मितानिनों, एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य संगठकों की टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी। इस दौरान कुष्ठ रोग के संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वचा पर सुन्न या हल्के रंग के धब्बे, हाथ-पैरों में संवेदना की कमी, नसों में सूजन अथवा कमजोरी जैसे लक्षणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय खोब्रागड़े ने बताया कि कुष्ठ रोग पूर्णत: उपचार योग्य बीमारी है तथा इसका उपचार सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि समय पर पहचान एवं नियमित उपचार से रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जी सकता है और विकलांगता की संभावना को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। जिला कुष्ठ नोडल अधिकारी डॉ. एसआर कोवाची ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे रोगियों की पहचान करना है, जो अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान एवं उपचार से न केवल रोगी को लाभ मिलता है, बल्कि समुदाय में संक्रमण के प्रसार को भी प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सर्वेक्षण दल को आवश्यक सहयोग प्रदान करें, कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों एवं सामाजिक भेदभाव से दूर रहें तथा किसी भी संदिग्ध लक्षण की जानकारी तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दें।

बेमेतरा में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि प्रकरण की जांच शुरू, कलेक्टर ने गठित की चार सदस्यीय समिति

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दिलाने के नाम पर कथित रूप से रिश्वत मांगने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। शिकायत प्राप्त होने के बाद कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदक विनय बंजारे, निवासी ग्राम सिंघनपुरी, जिला बेमेतरा द्वारा 11 जून 2026 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी बाबू के विरुद्ध ।शिकायत के आधार पर कलेक्टर कार्यालय द्वारा 12 जून 2026 को जांच समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया।

जांच समिति में वित्त शाखा की प्रभारी अधिकारी श्रीमती दिव्या पोटाई, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अभिषेक जायसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल

विकास विभाग चंद्रेश सिसोदिया तथा लीड बैंक अधिकारी सुशील सिंह को शामिल किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार समिति शिकायत की जांच के साथ-साथ मार्च 2026 से वतर्मान तक जारी संबंधित प्रकरणों एवं पात्रता संबंधी दस्तावेजों की भी जांच करेगी। समिति को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्ट अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि से जुड़े एक प्रकरण में न्यायालय परिसर में पदस्थ एक कर्मचारी पर राशि स्वीकृत कराने के नाम पर धनराशि मांगने के आरोप लगाए गए हैं।

मामले का वीडियो एवं अन्य तथ्य सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं। अब सभी की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी।

रेशम, खादी और हथकरघा क्षेत्र को नई दिशा : केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

बुनकरों और शिल्पियों की आय बढ़ाने के लिए डिजाइन प्रशिक्षण एवं नवाचार पर जोर, उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक वार्षिक आय दिलाने विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रेशम उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल देते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हथकरघा बुनकरों, शिल्पियों एवं कारीगरों को डिजाइन विकास संबंधी नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े तथा उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ के अध्यक्ष भोजराज देवांगन, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा, छत्तीसगढ़ माटी कला एवं हस्तशिल्प बोर्ड के प्रबंध संचालक जयप्रकाश मौर्य, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती लीना कमलेश मंडावी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की

वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों को निर्यात एजेंसियों से जोड़ा जाए तथा उनके उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल सके। बैठक में सिल्क एवं कॉटन उत्पादों में अन्य प्राकृतिक रेशों के समावेश के माध्यम से नवीन उत्पाद विकसित करने तथा बाजार विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

केंद्रीय मंत्री ने रेशम केंद्रों में रेशम पौधों के साथ फ्लोरीकल्चर एवं सब्जी उत्पादन की मिश्रित खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, जिससे कृमिपालकों एवं कीटपालकों की आय में अतिरिक्त वृद्धि हो सके। उन्होंने वस्त्र निर्माण में प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए हल्दी, कत्था, मेहंदी तथा विभिन्न पुष्पों से प्राप्त रंगों के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता बताई। साथ ही हथकरघा क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक डिजाइन एवं उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के सहयोग से कार्य करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम क्षेत्र के समग्र विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के विभिन्न उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुहर्रम पर डीजे, धुमाल, आतिशबाजी और स्वांग पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

एसपी कार्यालय में मुस्लिम समाज की बैठक, शांति-सौहार्द बनाए रखने की अपील

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहादर्पूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को मुस्लिम समाज की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई।

डीजे-बैंड पर रोक, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में हुई बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, एसडीएम गौतम पाटिल, नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो और उप पुलिस अधीक्षक के पी मरकाम मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि मुहर्रम में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

शेर या अन्य स्वांग पर भी रोक

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश के अनुसार मुहर्रम पर्व के दौरान शेर या अन्य का स्वांग धारण कर नृत्य, प्रदर्शन और गैर पारंपरिक गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जुलूस मार्ग और यातायात पर चर्चा

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, जुलूस मार्ग, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर दिशा निर्देश दिए गए। आयोजन समितियों और समाज के प्रतिनिधियों से शासन, प्रशासन और वक्फ बोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए शांति, अनुशासन और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई।

शहर में एनाउंसमेंट कराएगा प्रशासन

बैठक में तय हुआ कि शहर में एनाउंसमेंट कर शेर या अन्य स्वांग न बनाने की समझाइश दी जाएगी। ऐसा करने पर समाज जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशासन ने जिलेवासियों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है।

15-16वें वित्त की राशि नहीं मिलने से गांवों का विकास ठप : डॉ. चरणदास महंत

नेता प्रतिपक्ष बोले, भाजपा सरकार का खजाना खाली, सुशासन कहीं नहीं

नई दृष्टिबिंदु / अंबागढ़ चौकी

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15वें और 16वें वित्त की राशि नहीं मिलने से गांवों का विकास ठप है। सरकार का खजाना खाली है और विकास कार्य सिमट गए हैं।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के दौरे पर रहे महंत

डॉ. महंत गुरुवार को जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के एकदिवसीय दौरे पर रहे। ग्राम गोटाटोला में विधायक इंद्रशाह मंडावी ने उनका स्वागत किया। कांग्रेसजनों ने नारेबाजी के साथ स्वागत किया। उन्होंने मोहला-मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी और खुज्जी विधायक भोलाराम साहू के विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से भेंट की। अंबागढ़ चौकी में पूर्व विधायक तेजकुंवर नेताम और नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी से सौजन्य मुलाकात की।

'सरकार निकम्मी, सुशासन नहीं'

रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में डॉ. महंत ने कहा कि कांग्रेस शासन में मोहला को जिला और तीन तहसील बनाई गई। सरकार बदलने के बाद क्षेत्र की सुध नहीं ली जा रही। लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष की भूमिका पर उन्होंने कहा कि अब विधायक और पूर्व विधायकों के साथ आंदोलन और विरोध करेंगे। बेमेतरा में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कलेक्टर, एसपी को नसीहत देने का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी सुशासन नहीं है। सरकार पूरी तरह निकम्मी है।

'भाजपा नेता-अधिकारी लूट रहे'

विधायक निवास में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता और अधिकारी आम लोगों को लूट रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही। मध्यप्रदेश में गृहमंत्री रहते मानपुर थाना लूटने की घटना के बाद हेलिकॉप्टर से दौरा याद किया। झीरम हमले का जिक्र कर कहा कि कांग्रेस बलिदान देने वाली पार्टी है।

'आदिवासी विकास के समर्थक हैं महंत' : मंडावी

विधायक इंद्रशाह मंडावी ने कहा कि डॉ. महंत आदिवासी समाज के विकास के प्रबल समर्थक हैं। उनका सपना आदिवासी समाज को मजबूत बनाना है। भाजपा शासन में विकास ठप है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार से ही सर्वांगीण विकास संभव है।

100 से अधिक ग्रामीण कांग्रेस में शामिल

दौरे के दौरान मोहला, काड़े और भगवानटोला के 100 से अधिक ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रवेश किया। डॉ. महंत ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में शामिल किया। दौरे में पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, डॉ. विनय जायसवाल, तेजकुंवर नेताम, पूर्व मंत्री गोवर्धन नेताम, पूर्व विधायक छन्नी साहू और महेश चंद्रवंशी शामिल रहे।

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक पर चाकू से हमला, दो गिरफ्तार

दो नाबालिग भी हिरासत में, धारदार बटनदार हथियार जब्त

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मना करने पर युवक पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल दो नाबालिगों को भी अभिरक्षा में लिया गया है।

बीसीजी स्कूल मैदान के पास हुई वारदात

11 जून की रात करीब 10:30 बजे प्रार्थी लोकेश सोनी बीसीजी स्कूल मैदान के पास पिकअप खड़ी कर खड़ा था। तभी कुछ युवकों ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज की और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में लोकेश के बाएं हाथ में चोट आई। बीच बचाव करने आए गणेश सोनकर पर भी हमला किया गया।

लोकेश की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 221/2026 धारा 109, 296, 351(3), 118(1), 119(1) बीएनएस और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राम वर्मा, 19 वर्ष, निवासी कारगिल चौक रामनगर और राजबीर बघेल, 19 वर्ष, निवासी सत्यम बेकरी के पास रामनगर को गिरफ्तार किया। शास्त्री नगर के दो नाबालिगों को भी अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक धारदार बटनदार हथियार बरामद किया गया है।

न्यायालय में पेश

आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि घटना का कारण शराब के लिए पैसे मांगने पर हुआ विवाद था। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। कानून तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100